घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 307- बुधवार 09- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

धुरंधर के गाने पर पीएम मोदी की एंट्री

प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में जेन-जी से संवाद किया

वडोदरा,08 सितम्बर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में जेन-जी से 25 मिनट संवाद किया। मंच पर पहुंचते ही क्वीन का मशहूर गाना 'वी विल रॉक यू'बजाया गया। इसके बाद 'धुरंधर' का गाना 'आरी आरी' भी बजा। पीएम ने कहा...'लोग आपको झूठ की गूंज से गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सच्चाई के साथ खड़े रहना।' मोदी का यह बयान राहुल गांधी और कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' अभियान पर तंज माना जा रहा है।

मोदी बोले...पहले बजट में एक-दो ट्रेनों की घोषणा होती थीं...

पीएम ने कहा, 'पहले की सरकार में बजट में एक-दो ट्रेनों की घोषणा होती थी। उसके भी सालभर ढोल पीटे जाते थे। अब एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अब नई ट्रेन से वडोदरा,उदयपुर और आलीराजपुर के लोगों को सुविधा होगा। इस साल रेल बजट पौने 3 लाख करोड़ से ज्यादा रहा है। एक बार पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बन गया तो फिर रोजगार बढ़ना शुरू हो जाता है।' पीएम ने कहा, 'महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी का ये मैदान। अलग-अलग फील्ड में काम करने वाले साथियों का साथ, विकास का उत्सव, ये सब साथ हो रहा है। आज मैं विकसित भारत की यात्रा को और गति देने के लिए आपके बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले यहां देश के विकास से जुड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण-शिलान्यास हुआ। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं।'

पीएम ने कहा- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने काम की संस्कृति बदली : पीएम ने कहा, 'वडोदरा तो गतिशक्ति यूनिवर्सिटी का शहर है। आज यहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कड़िया जुड़ गई हैं। आज यहां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के लिए ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।' 'ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 2004 में विचार शुरू हुआ था। कई नौजवानों का तब जन्म भी नहीं हुआ था। 2006 में एक विशेष कंपनी बनाई गई, 2014 तक फाइलें ही यहां से वहां होती रहीं।

पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया

मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर से दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, एक संदिग्ध व्यक्ति ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताया था। जानकारी के मुताबिक, जांच के दौरान उसके पास पीएमओ कार्यालय का फर्जी पहचान पत्र भी मिला। जब सुरक्षा जांच की गई तो पहचान पत्र फर्जी पाए गए। जानकारी के मुताबिक, दूसरे संदिग्ध के पास बंदूक भी था। मामले में क्राइम ब्रांच आगे की जांच कर रही है। इन दोनों संदिग्धों का फर्जी पहचान पत्र और हथियार के साथ आने का क्या मकसद था, इसकी जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस ने बताया कि मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर से दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहां प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम भी प्रस्तावित था। पुलिस के मुताबिक, हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान 24 वर्षीय रोहन पारेख के रूप में हुई है। उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताया था। उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी था, जिसके पास बंदूक थी। मामले में क्राइम भ्रांच आगे की जांच कर रही है।

एआई युग के लिए युवाओं को तैयार करना जरूरी भारत को बनाना है वैश्विक महाशक्ति : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में दुनिया के सामने महाशक्ति बनना है तो देश को इसके लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि एआई में दक्ष युवाओं की जरूरत केवल सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, विनिर्माण और रोबोटिक्स सहित हर क्षेत्र में एआई नए समाधान और रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को एआई के लिए तैयार करने की दिशा में बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। 'नमो फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा विशेष कौशल हासिल कर उसका इस्तेमाल एआई के साथ मिलाकर नई तकनीक और समाधान विकसित कर सकता है। कोई युवा कृषि के लिए एआई समाधान तैयार कर सकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीक विकसित कर सकता है, विनिर्माण की उत्पादकता बढ़ा सकता है या अपना रोबोटिक्स स्टार्टअप शुरू कर सकता है। इसलिए भारत और दुनिया के उद्योगों की जरूरतों को समझने तथा एआई का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को तैयार करना जरूरी है। मोदी ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और वैश्विक जरूरतों के साथ शिक्षा और सीखने के तरीके भी बदल रहे हैं। पहले केवल डिग्री पर जोर था, अब कौशल का महत्व भी उतना ही बढ़ गया है। युवाओं के कौशल को लगातार उन्नत करना जरूरी है और इसी उद्देश्य से सरकार शिक्षा नीति तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की मेहनत की कमाई बचाने के लिए सरकार छात्रों को देश के श्रेष्ठ शिक्षकों से मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए ऐसी कनेक्टिविटी जरूरी है, जो सुगम होने के साथ समय की जरूरत के अनुरूप तेज भी हो। उन्होंने कहा कि वडोदरा गतिशक्ति विश्वविद्यालय का शहर है और आज यहां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अंतिम कड़ियां भी जुड़ गई हैं। मोदी ने हाल में मुंबई के जेएनपीटी बंदरगाह से वडोदरा तक चली डबल-स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का उल्लेख करते हुए कहा कि एक बार में 250 से अधिक ट्रकों के बराबर सामान पहुंचाया गया।

संक्षिप्त समाचार

आईएएस अनिल डामोर का निधन विदिशा से भोपाल हुआ था ट्रांसफर

विदिशा,08 सितम्बर 2026। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक महकमे से दुखद खबर सामने आई है। 2019 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार डामोर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। मंगलवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।नए स्थान तलाशें जानकारी के अनुसार,अनिल डामोर विदिशा स्थित अपने शासकीय आवास के बाथरूम में अचानक बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। अनिल कुमार डामोर विदिशा में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। इसी महीने राज्य शासन की ओर से उनका तबादला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,भोपाल में उप सचिव के पद पर किया गया था। नई जिम्मेदारी संभालने से पहले ही उनके निधन की खबर सामने आने से प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में शोक की लहर है।

भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन हुआ उग्र,सड़कों पर लगा जाम

भोपाल,08 सितम्बर 2026 । भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन मंगलवार को और तेज हो गया। रातभर प्रदर्शन करने के बाद डॉक्टर सुबह भी सड़क पर डटे रहे। डॉक्टरों के सड़क पर बैठने से पॉलिटेक्निक चौराहे से हमीदिया अस्पताल तक यातायात प्रभावित रहा और लंबा जाम लग गया। इस दौरान अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी परेशानी उठानी पड़ी। प्रदर्शन के कारण लगे जाम में मरीजों को लेकर पहुंच रही एंबुलेंस भी फंस गई। एंबुलेंस में मरीज होने के बावजूद रास्ता जल्द साफ नहीं हो सका। इससे मरीज और उसके परिजनों की चिंता बढ़ गई। अस्पताल पहुंचने वाले दूसरे मरीजों को भी जाम का सामना करना पड़ा।

महाराष्ट्र के गोंदिया में मजदूरों से भरी बोलेरो को ट्रक ने मारी टक्कर, मध्य प्रदेश के 6 लोगों की मौत

महाराष्ट्र,08 सितम्बर 2026। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में मंगलवार को गोंदिया-बालाघाट नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। नागरा के पास हुए इस हादसे में तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो पैसेंजर वाहन की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

अमोरा के पास आमने-सामने भिड़े ट्रक और बोलेरो

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, ट्रक गोंदिया से बालाघाट की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। इसी दौरान अमोरा के पास सामने से आ रही बोलेरो पैसेंजर गाड़ी से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आईं।

स्थानीय लोगों ने घायलों को वाहन से बाहर निकाला : पुलिस के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्षतिग्रस्त बोलेरो में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। पुलिस ने भी स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला। इसके बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना के बाद कुछ समय तक घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

टक्कर के बाद मौके पर मची चीख-पुकार

भीषण टक्कर के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना की आवाज और लोगों के शोर को सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों ने बिना देर किए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। हादसे की सूचना पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

हादसे में छह यात्रियों की मौके पर मौत

पुलिस के अनुसार,दुर्घटना में छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया,जहां उनका इलाज जारी है। गंभीर घायलों की स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है।

आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से झटका अंतरिम जमानत याचिका हुई खारिज

अहमदाबाद,08 सितम्बर 2026। नाबालिग से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले में जेल की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसुमल उर्फ आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी ओर से दाखिल अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आसाराम ने यह अर्जी राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट से मिली 20 दिनों की पैरोल के आधार पर दायर की थी। उनका उद्देश्य गुजरात में दर्ज यौन शोषण के मामले के चलते जेल से रिहाई में आ रही कानूनी बाधा को दूर कराना था।

पैरोल मिलने के बाद भी नहीं हो पाई रिहाई : हाल ही में जोधपुर हाईकोर्ट ने आसाराम को स्वास्थ्य संबंधी कारणों को देखते हुए 20 दिनों की पैरोल प्रदान की थी। हालांकि, पैरोल आदेश मिलने के बावजूद जेल प्रशासन ने उनकी रिहाई रोक दी। प्रशासन की ओर से गुजरात में दर्ज सूरत यौन शोषण मामले को इसकी वजह बताया गया। इस कानूनी अड़चन के चलते आसाराम पैरोल का लाभ उठाकर जेल से बाहर नहीं आ सके। जेल से बाहर आने का रास्ता साफ कराने के लिए आसाराम के वकीलों ने गुजरात हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग की। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। इसके बाद कोर्ट ने आसाराम को फिलहाल राहत देने से इनकार करते हुए उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। फैसले के बाद उनकी जेल से बाहर आने की उम्मीदों को एक और झटका लगा है। आसाराम का पूरा नाम आसुमल सिरुमलानी हरपलानी है। उनका जन्म 17 अप्रैल 1941 को हुआ था। उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशों में भी आश्रमों का नेटवर्क खड़ा किया था।

मोदी मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज

मुंबई,08 सितम्बर 2026। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीएम मोदी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने 2019 में जारी मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने निचली अदालत में मानहानि की शिकायत पर सुनवाई छह हफ्ते तक टालने का आदेश बढ़ा दिया। इससे राहुल को इस दौरान मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए समय मांगा था। दरअसल, राहुल ने 2018 में राजस्थान की एक सभा में राफेल विमान डील पर पीएम को 'चौकीदार चोर है' कहा था। आरोप है कि उन्होंने 24 सितंबर को एक्स पर वीडियो पोस्ट कर मोदी को कमांडर-इन-थीफ यानी चोरों का सरदार कहा था। इस

मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 28 अगस्त 2019 को मानहानि की शिकायत पर राहुल के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। राहुल ने इस आदेश को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश..बना वैधानिक योग्यता शिक्षक भर्ती पर रोक

नई दिल्ली,08 सितम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित वैधानिक योग्यता पूरी किए बिना किसी शिक्षक या ट्यूटर को स्कूल अथवा कॉलेज में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे शिक्षकों को बाद में सरकारी सेवा में समायोजित करने की अनुमति भी नहीं होगी। अदालत ने शिक्षा व्यवस्था में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति को अनिवार्य बताते हुए गुणवत्ता से समझौता नहीं करने की बात कही है। चीफ जस्टिस सूर्य

कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी। मोहन की पीठ ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान RTE Act, NCTE Act और GC Act के तहत निर्धारित योग्यता और नियमों का पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक शिक्षक की नियुक्ति केवल किसी संस्थान की जरूरत के आधार पर नहीं हो सकती, बल्कि उम्मीदवार का निर्धारित मानकों को पूरा करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा की गुणवत्ता को संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने का अधिकार मौलिक अधिकार के दायरे में आता है। इसलिए शिक्षकों की नियुक्ति में ऐसे किसी भी तरीके को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका हो। यह मामला असम सरकार की एक ऐसी योजना से जुड़ा है, जिसमें निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल करने का प्रावधान बताया गया है। इसी व्यवस्था को लेकर राजेश चौहान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में इस योजना की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बताया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को बिना निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी भर्ती प्रक्रिया के सीधे सरकारी सेवा में शामिल करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हो सकता है।

संपादकीय

जहरीली शराब का कहर

मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 20 से अधिक लोगों की मौत यही बता रही है कि अपने देश में समय के साथ कुछ समस्याएं किस तरह विकराल और जानलेवा होती जा रही हैं। यह शर्मनाक है कि रह-रहकर देश के किसी न किसी हिस्से में जहरीली शराब से मौतों का कोई न कोई मामला सामने आता ही रहता है। आम तौर पर शासन-प्रशासन तभी चेतता है, जब मरने वालों की संख्या अधिक होती है।

विडंबना यह है कि इसके बाद भी स्थितियां सुधरती नहीं। जहरीली शराब बनाने-बेचने वालों की गिरफ्तारी के साथ लापरवाह अधिकारियों का निलंबन होता है,लेकिन कुछ समय बाद फिर कहीं और कई बार तो उसी राज्य में जहरीली शराब कहर ढा देती है। मध्य प्रदेश से पहले गुजरात और बिहार में कई लोग जहरीली शराब पीने से मरे थे। इसके पहले महाराष्ट्र में। आम तौर देसी तरीके से बनाई जाने वाली शराब ही जहरीली शराब में तब्दील हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है,क्योंकि इसे बनाने वाले ज्यादा कमाई के चक्कर में ऐसे तौर-तरीके अपनाते हैं,जो जानलेवा साबित होते हैं। एक समय था,जब देसी शराब महुआ और कुछ अनाजों के जरिये प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती थी,लेकिन अब वह घातक रसायनों के जरिये बनाई जाने लगी है। यही शराब प्रायः जहरीली हो जाती है।

अपने देश में शराब को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताए जाने के बाद भी उसका चलन तो बढ़ता जा रहा है,लेकिन उसकी गुणवत्ता का कोई भरोसा नहीं। अभी हाल में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआइ ने यह निर्देश दिया कि एक प्रचलित रम को इसी श्रेणी में नहीं बेचा जा सकता,क्योंकि उसे निर्धारित तरीके से बनाने के स्थान न्यूट्रल स्पिरिट में आर्टिफिशियल रम फ्लेवर मिलाकर बनाया और बेचा जा रहा है।

यह गनीमत है कि एफएसएसएआइ को भारत में बनने वाली विदेशी शराब की गुणवत्ता को लेकर चिंता हुई, लेकिन क्या वह देसी शराब की भी गुणवत्ता परखेगा? इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां जहरीली शराब बनाने और बेचने वाले माफिया की कमर तोड़ने में कब कामयाब होंगी? वे इससे अपरिचित नहीं हो सकतीं कि अवैध तरीके से देसी शराब बनाने का काम एक कुटीर उद्योग जैसा रूप ले चुका है।

कभी-कभी ऐसा लगता है कि जहरीली शराब के लगातार कहर ढाने के बाद भी शासन-प्रशासन इसलिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं उठाता,क्योंकि उसकी चपेट में आने वाले आम तौर पर दीन-हीन लोग होते हैं। यह समझा जाए कि इस तरह की घटनाएं केवल कानून के शासन को कमजोर ही नहीं करतीं,बल्कि देश की बदनामी भी कराती हैं। यह ठीक नहीं कि आज जब देश को विकसित बनाने की बातें हो रही हैं, तब वैसी घटनाएं हो रही है,जैसी कई निर्धन देशों में भी नहीं होतीं।

जो व्यक्ति सबका मित्र होता है,
असल मे वह किसी का मित्र नहीं होता।
-अरस्तू

मौत का इंतजार करती इमारतें और गहरी नींद सोता प्रशासन

जर्जर इमारतों से ज्यादा जर्जर है निगरानी का सिस्टम

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,नई दिल्ली

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में जो हृदयविदारक घटना घटित हुई है,वह केवल एक पांच मंजिला इमारत के भरभराकर गिरने की घटना नहीं बल्कि राजधानी की उस व्यवस्था का ढ़हना है,जिसकी नींव नागरिकों की सुरक्षा, कानून के शासन और प्रशासनिक जवाबदेही पर टिकी होनी चाहिए थी। जिस इमारत में कुछ घंटे पहले तक देश के अलग-अलग हिस्सों से आए युवा अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे,देखते ही देखते वह ईंट,सीमेंट और लोहे के मलबे में बदल गई। धूल का गुबार तो छंट जाएगा,मलबा भी हट जाएगा,सड़कें फिर सामान्य हो जाएंगी लेकिन उन परिवारों के जीवन में जो शून्य पैदा हुआ है,वह कभी नहीं भर सकेगा। 'हॉस्टल डेज' नामक लड़कों के लिए बने पीजी की इस पांच मंजिला इमारत में हादसे के वक्त कई छात्र अपने कमरों में थे,जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इमारत लगभग 40-50 वर्ष पुरानी थी और हादसे के समय बेसमेंट में मरम्मत तथा खुदाई का काम चल रहा था। यही तथ्य इस त्रासदी को और भयावह बना देता है।

सवाल केवल यह नहीं है कि इमारत क्यों गिरी बल्कि असली सवाल यह है कि इतनी पुरानी और संवेदनशील इमारत में बेसमेंट की खुदाई और निर्माण संबंधी गतिविधियां आखिर चल कैसे रही थी? हर बड़े भवन हादसे के बाद एक ही कहानी दोहराई जाती है। प्रशासन कहता है कि जांच होगी,कुछ छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई होती है और कुछ दिनों बाद पूरा मामला फाइलों के नीचे दब जाता है। फिर किसी दूसरे इलाके में कोई और इमारत गिरती है,कहीं आग लगती है, कोई बेसमेंट मौत का कुआं बन जाता है और हम फिर वही प्रश्न पूछते रह जाते हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है? सच तो यह है कि भारत के शहरों में कोई बहुमंजिला

अवैध निर्माण रातों-रात खड़ा नहीं होता। जमीन का उपयोग बदलता है,नक्शा बनता है,निर्माण शुरू होता है,मंजिलें बढ़ती हैं,बिजली-पानी के कनेक्शन मिलते हैं और अंततः उस इमारत में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अनेक विभागों और अधिकारियों की भूमिका होती है। ऐसे में यह कहना कि प्रशासन को कुछ पता ही नहीं था, जिम्मेदारी से बचने का सबसे आसान बहाना है।

यदि कोई इमारत नियमों के विरुद्ध बन रही थी तो निर्माण के दौरान संबंधित नगर निगम अधिकारी कहां थे? यदि वहां व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी तो फायर विभाग ने सुरक्षा का आकलन क्यों नहीं किया? बिजली और पानी के कनेक्शन किस आधार पर मिले? पुलिस और स्थानीय प्रशासन की नजर उस भवन पर क्यों नहीं पड़ी? और यदि सब कुछ नियमों के अनुसार था तो फिर हादसा हुआ कैसे?यही वे प्रश्न हैं, जिनका जवाब केवल ठेकेदार या किसी छोटे कर्मचारी को दोषी ठहराकर नहीं दिया जा सकता। सत्य निकेतन की त्रासदी इसलिए भी गंभीर है क्योंकि दिल्ली में पीजी संस्कृति तेजी से बढ़ी है। देशभर से राजधानी में पढ़ने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और रोजगार तलाशने आने वाले हजारों युवा ऐसी इमारतों में रहते हैं,जहां कमरे छोटे हैं, गलियां संकरी हैं, सीढ़ियां संकरी हैं और सुरक्षा मानकों की स्थिति अक्सर संदिग्ध रहती है। मकान मालिक के लिए कमरों की संख्या बढ़ाना कारोबार है लेकिन उस कमरे में रहने वाला छात्र अपने सपने लेकर वहां आता है। जब छह कमरों की अनुमति वाली इमारत में 25 से अधिक कमरे बना दिए जाते हैं, जब बेसमेंट को पार्किंग के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब एक ही निकास मार्ग पर सैंकड़ों लोगों की सुरक्षा निर्भर कर दी जाती है, तब यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं रहता,यह मानव जीवन के साथ खिलवाड़ बन जाता है।

दिल्ली में अतीत की त्रासदियां भी हमें बार-बार चेताती रही हैं। 1997 का उपहार सिनेमा अग्निकांड हो या हाल के वर्षों में सामने आए बेसमेंट,कोचिंग सेंटर और व्यावसायिक इमारतों से जुड़े हादसे, हर घटना के बाद सुरक्षा मानकों पर सवाल उठे। बंद दरवाजे,अवरुद्ध निकास, अवैध निर्माण,अग्निशमन उपकरणों की अनुपलब्धता और प्रशासनिक उदासीनता बार-बार त्रासदियों की पृष्ठभूमि में दिखाई देती रही है। फिर भी व्यवस्था की स्मृति इतनी कमजोर है कि कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर पुराने ढ़र्रे पर लौट आता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सस्पेंशन हमेशा छोटे कर्मचारी का ही क्यों होता है? यदि किसी इलाके में वर्षों तक अवैध निर्माण चलता रहा, यदि नियमों के विपरीत इमारतें खड़ी होती रही और उनमें पीजी, कोचिंग सेंटर, दुकानें या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चलती रही तो उस पूरे प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही तय होनी चाहिए,जिसने इसे होने दिया। तत्कालीन अवैध निर्माण प्रभारी,संबंधित वरिष्ठ अधिकारी,जोनल स्तर के जिम्मेदार अधिकारी और संबंधित विभागों की भूमिका की निष्पक्ष जांच क्यों न हो? यदि मिलीभगत प्रमाणित होती है तो कार्रवाई भी उसी अनुपात में कठोर क्यों न हो?

समस्या किसी एक इमारत की नहीं है। दिल्ली और देश के तमाम शहरों में हजारों ऐसी इमारतें हैं,जो बाहर से सामान्य दिखाई देती हैं लेकिन भीतर से मौत के जाल में बदल चुकी हैं। कहीं बेसमेंट में अवैध निर्माण है,कहीं बिना वेंटिलेशन के कोचिंग सेंटर,कहीं संकरी सीढ़ियां,कहीं बंद खिड़कियां,कहीं लोहे की ग्रिलें और कहीं एक ही प्रवेश-निकास द्वार। अग्निशमन उपकरण कई जगह केवल निरीक्षण के समय दिखाने के लिए रखे जाते हैं और आपातकालीन निकास कागजों पर मौजूद रहते हैं, वास्तविकता में नहीं। ऐसी स्थिति में हादसा होने पर दमकल की गाड़ियां भी संकरी गलियों में फंस जाती हैं। बचाव दल के पास पहुंचने का रास्ता नहीं होता और अंदर फंसे लोगों के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। फिर कुछ ही मिनटों में एक इमारत कब्रिस्तान में बदल जाती है।

अब जरूरत केवल दोषी खोजने की नहीं, व्यवस्था बदलने की है। दिल्ली की सभी पुरानी बहुमंजिला और व्यावसायिक इमारतों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। पीजी,हॉस्टल,कोचिंग सेंटर और बेसमेंट में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अनिवार्य जांच होनी चाहिए। फायर एनओसी की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध हो। अवैध निर्माण पर केवल जुर्माना लगाकर उसे वैध बनाने की प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। गंभीर उल्लंघन वाली इमारतों को तत्काल सील और आवश्यकतानुसार ध्वस्त किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह कि जिम्मेदारी ऊपर तक जानी चाहिए। किसी दुर्घटना के बाद दो-चार छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर देना प्रशासनिक कार्रवाई नहीं,अक्सर जिम्मेदारी से बचने का तरीका बन जाता है। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही, मिलीभगत या भ्रष्ट आचरण के कारण लोगों की जान जोखिम में पड़ी है तो उसके विरुद्ध कठोर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। पद जितना बड़ा हो,जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए।

सत्य निकेतन का मलबा केवल ईंट-पत्थरों का ढ़ेर नहीं है। उसके नीचे प्रशासनिक दावों की विश्वसनीयता,भवन सुरक्षा के नियमों और नागरिकों के भरोसे की भी परीक्षा हो रही है। इस त्रासदी को 'हादसा' कहकर आगे बढ़ जाना सबसे बड़ा अपराध होगा। हादसा वह होता है, जिसे रोका न जा सके लेकिन जिस दुर्घटना की जमीन अवैध निर्माण, नियमों की अनदेखी,भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही से तैयार होती है,उसे केवल हादसा कहना सच्चाई को छोटा करना है। यदि इस बार भी जांच के नाम पर खानापूर्ति हुई,छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराकर बड़े जिम्मेदार बच निकले और कुछ लाख रुपये के मुआवजे को न्याय का विकल्प बना दिया गया तो अगली त्रासदी केवल समय की प्रतीक्षा करेगी। तब फिर कोई इमारत गिरेगी, कोई परिवार उजड़ेगा,कोई बच्चा मलबे में दबेगा और हम फिर पूछेंगे कि आखिर असली गुनहगार कौन है? जबकि सच हम सभी जानते होंगे। गुनहगार केवल वह व्यक्ति नहीं होगा,जिसने अवैध निर्माण किया बल्कि गुनहगार वह पूरा तंत्र होगा, जिसने उसे बनने दिया,चलने दिया और तब तक आंखें बंद रखी,जब तक मलबे ने चीखना शुरू नहीं कर दिया। अब समय चीख सुनने का नहीं,व्यवस्था को जवाबदेह बनाने का है।

हवा की परीक्षा में शहर टॉप,साँसों की कॉपी कौन जाँचेगा?

हवा का हिसाब कागज पर, दर्द का हिसाब फेफड़ों में...

लखनऊ ने हवा सुधार ली,अब नागरिक अपनी साँस सुधारें

प्रो.आर.के.जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

लखनऊ ने करोड़-प्लस आबादी वाले शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का नंबर-एक तमगा हासिल कर लिया है। बधाई! अब शायद हवा भी सरकारी प्रमाणपत्र लेकर चलेगी–देखिए,मैं देश की सबसे साफ हवा हूँ। खबर खुशी देती है, मगर पीछे एक कड़वी हँसी भी सुनाई देती है। हमारे यहाँ रैंकिंग का बड़ा जलवा है। नंबर मिलते ही उपलब्धि,प्रमाण-पत्र मिलते ही समस्या खत्म! लखनऊ स्वच्छ वायु का सम्राट घोषित है। मगर असली सवाल दरबार के बाहर खड़ा है–यह ताज हवा के लिए है या रिपोर्ट के लिए? नागरिक हवा साँस में भरता है,व्यवस्था उसे आंकड़ों में।

एक समय था जब शहर अपनी तहजीब,संस्कृति और पहचान से जाने जाते थे। अब महानगरों की नई पहचान है–कौन कितनी जहरीली हवा देता है। दिल्ली इस दौड़ में लंबे समय से चर्चित रही, मुंबई, कोलकाता और कानपुर भी पीछे नहीं रहे। ऐसे माहौल में लखनऊ का नंबर-एक पर पहुँचना सुखद है।

विशेषज्ञों के अनुसार साफ परिवहन, धूल नियंत्रण, बेहतर कचरा प्रबंधन और हरियाली बढ़ाने के प्रयासों ने यह उपलब्धि दिलाई है। इन प्रयासों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन सड़क पर निकलते ही एक दूसरा विशेषज्ञ मिलता है...आम नागरिक। उसकी आँखों में धूल,नाक में धुआँ और साँस में जलन है। वह पूछता है...अगर हवा सचमुच साफ हो गई है, तो मेरा अनुभव अब भी इतना धुँधला क्यों है?

सरकारों को रैंकिंग से बड़ा प्रेम है। नंबर-एक मिलते ही भाषणों के फूल खिलते हैं,कैमरे चमकते हैं और उपलब्धियों की सूची लंबी हो जाती है। लगता है,जैसे प्रदूषण ने खुद आत्म समर्पण कर दिया हो। मगर शहर की असली परीक्षा सभागार में नहीं, रिक्शा खींचते आदमी की साँस में होती है। स्कूल जाते बच्चे के सीने में होती है। उस बुजुर्ग की सुबह की सैर में होती है,जिसे थोड़ी दूर चलते ही खाँसी घेर लेती है। सवाल सीधा है...क्या उनकी साँस अब आसान हुई? अगर नहीं,तो रैंकिंग खुशी की खबर जरूर है,पर सफलता की मुहर अभी बाकी है।

हमारी व्यवस्था की अद्भुत कला है...बीमारी मिटाने से पहले उसकी रिपोर्ट सुधार देना। आदमी बीमार हो तो दवा चाहिए,मगर थर्मामीटर बदल देने से कागज पर बुखार जरूर उतर सकता है। प्रदूषण के मामले में खतरा यही है। आंकड़े सुधरें,अच्छी बात है;मगर हवा सुधरे,असली बात यह है। जिस बच्चे को अस्थमा की दवा चाहिए,उसके सामने नंबर-एक की रैंकिंग रख देने से सीना स्वस्थ नहीं होगा। जिस माँ को बच्चे को स्कूल भेजते समय मास्क पहनाना पड़े,उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कोई पदक नहीं,बच्चे की बेफिक्र साँस है। आंकड़ा तभी सार्थक है,जब उसका असर इंसान की जिंदगी में दिखे।

हरियाली बढ़ाने की घोषणाएँ हुईं,पेड़ लगाए गए। मगर सवाल है...कितने पेड़ बने और कितने सिर्फ तस्वीरों में खड़े रह गए? धूल रोकने के लिए सड़कों पर पानी छिड़का जाता है। पानी सूखते ही धूल फिर नाचने लगे तो यह इलाज नहीं, धूल को थोड़ी देर की छुट्टी है। कचरा प्रबंधन के वाहन दौड़ते हैं,मगर नाले कचरे से पटे रहें तो सफाई अधूरी है। इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण घटाने की अच्छी पहल हैं,लेकिन पूरा शहर ट्रैफिक जाम में फँसा हो तो समस्या सिर्फ बस के इंजन की नहीं,पूरी यातायात व्यवस्था की है। हवा साफ करनी है तो एक स्रोत नहीं,प्रदूषण की पूरी श्रृंखला पर प्रहार करना होगा।

हमने जीवन को आंकड़ों में बदलने की ऐसी आदत डाल ली है कि अब खुशहाली का सूचकांक है और हवा की भी रैंकिंग। संख्या जरूरी है,क्योंकि मापे बिना सुधार का पता नहीं चलता। मगर संख्या को जीवन का पर्याय मान लेना भूल है। लखनऊ का नागरिक अखबार में पढ़ता है कि उसके शहर की हवा नंबर-एक है और उसी सुबह धूल से बचकर सड़क पार करता है। रात को खाँसी आए तो अखबार की वह खबर गले नहीं उतरती। यहीं आंकड़े और अनुभव आमने-सामने खड़े होते हैं। शहर सेंसर और सर्वेक्षण से नहीं, उसमें बसने वाले लोगों की साँस से सचमुच साफ साबित होता है।

फिर भी लखनऊ की उपलब्धि को कमतर आँकना उचित नहीं। किसी शहर ने प्रदूषण के विरुद्ध कदम उठाए हैं तो उसकी सराहना होनी चाहिए। साफ परिवहन,धूल नियंत्रण,कचरा प्रबंधन और हरियाली की दिशा में हुए कामों को और मजबूत करना होगा। मगर नंबर-एक को मंजिल मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी। यह पुरस्कार उत्सव से अधिक जिम्मेदारी का प्रमाण बने। ताज मिल गया है तो अब उसे चमकाने से ज्यादा उसके नीचे के सिर को सुरक्षित रखने की चिंता होनी चाहिए। वरना तस्वीर वही रहेगी–सिर पर सोने का मुकुट और फेफड़ों में धूल।

स्वच्छ वायु का सबसे सच्चा सर्वेक्षण किसी कार्यालय में नहीं,हर नागरिक के सीने में होता है। जब बच्चा बिना खाँसे खुले मैदान में खेल सके,बुजुर्ग बिना साँस फूले सुबह टहल सके,मजदूर दिनभर मेहनत करके भी हवा को अपना दुश्मन न समझे...तभी मानिए लखनऊ सचमुच नंबर-एक है। रैंकिंग उपलब्धि है,लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है। लखनऊ ने कागज पर पहला स्थान पा लिया;अब उसे यह स्थान लोगों की साँस में दर्ज करना है। कागज की जीत पर तालियाँ बज सकती हैं,मगर दिल तभी खुश होता है जब साँस बेखौफ हो। शहर की सबसे बड़ी रैंकिंग यही है...उसके नागरिक कितनी आजादी से साँस लेते हैं।

भाषाई पुनर्गठन : विविधता को स्वीकार कर मजबूत हुई भारतीय एकता

डॉ. सत्यवान सौरभ,भिवानी,हरियाणा

स्वतंत्रता के समय भारत के सामने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को स्थायी बनाने की चुनौती नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण भी करना था जिसमें भाषा,संस्कृति,परंपरा और क्षेत्रीय पहचान की असाधारण विविधता के बावजूद राष्ट्रीय एकता कायम रहे। ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली प्रांतीय सीमाएँ प्रशासनिक सुविधा और औपनिवेशिक हितों के अनुरूप थीं। इनमें अनेक क्षेत्रों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग स्वाभाविक रूप से उठी।

हालाँकि शुरुआती दौर में राष्ट्रीय नेतृत्व भाषाई राज्यों को लेकर आशंकित था। विभाजन की त्रासदी अभी ताजा थी और यह भय था कि यदि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया तो क्षेत्रीय पहचान राष्ट्रीय पहचान पर हावी हो सकती है। किंतु भारतीय लोकतंत्र की विशेषता यही रही कि उसने इन आकांक्षाओं को दबाने के बजाय संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से समायोजित करने का रास्ता चुना। समय ने सिद्ध किया कि भाषाई पहचान को सम्मान देना भारत की एकता के लिए खतरा नहीं, बल्कि उसकी मजबूती का आधार बन सकता है। भाषाई पहचान की राजनीतिक स्वीकार्यता स्वतंत्रता से पहले ही दिखाई देने लगी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रांतीय संगठनों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया था। इसका उद्देश्य यह था कि जनता से संवाद उनकी भाषा और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में बेहतर ढंग से हो सके। लेकिन

स्वतंत्रता और विभाजन के बाद परिस्थितियाँ बदल गईं। राष्ट्रीय नेतृत्व तत्काल किसी बड़े क्षेत्रीय पुनर्गठन के पक्ष में नहीं था।

1948 में गठित धार आयोग ने तत्काल भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा नहीं की। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू,वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की सदस्यता वाली जेवीपी समिति ने भी 1949 में राष्ट्रीय एकता,प्रशासनिक स्थिरता और नवगठित राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उस समय यह सावधानी समझ में आती थी,क्योंकि देश राजनीतिक संक्रमण और सामाजिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था।

लेकिन जन आकांक्षाओं को अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता था। आंध्र क्षेत्र में तेलुगु भाषी जनता के लिए अलग राज्य की मांग तेज होती गई। पोट्टि श्रीरामुलु के 1952 के आमरण अनशन और उनकी मृत्यु ने इस आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया। व्यापक जनदबाव के बाद 1953 में आंध्र राज्य का गठन हुआ। यह घटना केवल एक राज्य के निर्माण तक सीमित नहीं रही,बल्कि इसने देश के अन्य हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को गति दी। इसके बाद सरकार ने समस्या का व्यापक और संस्थागत समाधान खोजने का प्रयास किया। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग,जिसकी अध्यक्षता फज़ल अली ने की,ने भाषाई और सांस्कृतिक आकांक्षाओं के साथ-साथ प्रशासनिक,आर्थिक तथा भौगोलिक व्यवहार्यता पर भी विचार किया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम तथा संविधान का सातवाँ संशोधन लागू हुआ। इसके परिणामस्वरूप भारत के प्रशासनिक मानचित्र में व्यापक बदलाव आया और 14 राज्यों तथा छह केंद्रशासित प्रदेशों की व्यवस्था अस्तित्व में आई।

भाषाई राज्यों का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि उन्होंने क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय पहचान के बीच टकराव को कम किया। जब किसी समुदाय को अपनी भाषा,संस्कृति और स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशासनिक पहचान मिली तो अलगाव की भावना कमजोर हुई। लोगों को यह विश्वास मिला कि भारतीय संघ उनकी विशिष्ट पहचान को समाप्त करने के बजाय उसका सम्मान करता है।

भाषाई पुनर्गठन का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ प्रशासनिक स्तर पर दिखाई दिया। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शासन-प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता ने राज्य और नागरिक के बीच दूरी कम की। लोकतंत्र तभी प्रभावी होता है जब नागरिक शासन की भाषा और प्रक्रिया को समझ सके। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशासन ने सामान्य नागरिकों की भागीदारी को अधिक सहज बनाया। इस व्यवस्था ने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को भी व्यापक बनाया। स्थानीय भाषा बोलने वाले राजनीतिक नेतृत्व को राज्य स्तर पर उभरने का अवसर मिला। इससे राजनीति अधिक जनसरोकारों से जुड़ी और विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएँ राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनीं। भाषाई राज्यों ने यह भी सिद्ध किया कि संघीय व्यवस्था में अलग-अलग क्षेत्रीय पहचानें राष्ट्रीय एकता के साथ सह-अस्तित्व रख सकती हैं। भारत का पुनर्गठन 1956 पर समाप्त नहीं हुआ। बदलती राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार राज्यों की सीमाओं में आगे भी परिवर्तन हुए। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन तथा 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के साथ हरियाणा का निर्माण इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि भारतीय संघ कोई स्थिर और अपरिवर्तनीय प्रशासनिक ढाँचा नहीं,बल्कि लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढालने वाली व्यवस्था है।

हालाँकि भाषाई राज्यों की सफलता का अर्थ यह नहीं कि भाषाई अस्मिता से जुड़ी सभी चुनौतियाँ समाप्त हो गईं। भाषाई बहुसंख्यकवाद,अल्पसंख्यक भाषाओं की उपेक्षा और क्षेत्रीय श्रेष्ठताबोध जैसी प्रवृत्तियाँ संघीय सद्भाव के लिए चुनौती बन सकती हैं। इसलिए भाषाई पहचान के संरक्षण के साथ भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संवैधानिक और लोकतांत्रिक माध्यमों से सुना जाए। किसी भी क्षेत्र की पहचान को राष्ट्र-विरोधी मानना उतना ही अनुचित है जितना क्षेत्रीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ऊपर रखना।

जर्मनी में कट्टरपंथी एएफडी की छोटी जीत के बड़े मायने

संजय सक्सेना,लखनऊ,

आजकल जर्मनी में अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड (एएफडी) की एक छोटी-सी जीत की बड़ी चर्चा हो रही है। एएफडी की छोटी-सी जीत से पूरे यूरोप और खासकर इस्लामी जगत में बेचैनी नजर आ रही है। यह जर्मनी की एक ऐसी धुर दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी है, जिसने हाल के वर्षों में जर्मन राजनीति में भूचाल ला दिया है। 2013 में स्थापित हुई इस पार्टी ने प्रवासियों के विरोध,यूरोपीय संघ (ईयू) के प्रति अविश्वास और जर्मन राष्ट्रवाद के दम पर देश के चुनावी परिदृश्य को बदलकर रख दिया है। अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड की स्थापना 6 फरवरी 2013 को हुई थी। शुरुआत में, इस पार्टी का गठन अर्थशास्त्रियों और बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया था, जो मुख्य रूप से यूरोपीय संघ की आर्थिक नीतियों,विशेष रूप से यूरो क्षेत्र के आर्थिक सहायता पैकेज के खिलाफ थे। हालांकि, 2015 के यूरोपीय शरणार्थी संकट के दौरान पार्टी की विचारधारा में एक बड़ा बदलाव आया। पार्टी ने अपना रुख पूरी तरह से धुर दक्षिणपंथी और लोकलुभावन बना लिया। इस विचारधारा के तहत पार्टी का सबसे प्रमुख एजेंडा देश में शरणार्थियों और प्रवासियों के आने पर पूर्ण विराम लगाना है। पार्टी अवैध शरणार्थियों को तेजी से निर्वासित करने की वकालत करती है। उनका मानना है कि प्रवासियों के आने से जर्मनी की पारंपरिक और सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। वे स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने जैसी नीतियों को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही पार्टी खुले तौर पर जर्मनी में बढ़ते इस्लामीकरण और बहुसंस्कृतिवाद का विरोध करती है। जर्मनी की खुफिया एजेंसी की रिपोर्टों के अनुसार, इसके नेताओं द्वारा कई बार जनविरोधी और नस्लवादी बयान दिए गए हैं। पार्टी यूरोपीय संघ की मौजूदा व्यवस्था में बड़े बदलाव या उससे पूरी तरह बाहर निकलने की बात भी करती है।

धार्मिक रुख की बात करें तो आधिकारिक तौर पर एएफडी स्वयं को ईसाई-यहूदी संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता का रक्षक मानती है। पार्टी का राजनीतिक दर्शन पारंपरिक यूरोपीय ईसाई मूल्यों पर आधारित है। पार्टी पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं,जैसे एक पुरुष और एक महिला का विवाह,और रूढ़िवादी ईसाई सामाजिक मूल्यों का पुरजोर समर्थन करती है। वे प्रगतिशील या आधुनिक उदारवादी विचारों,जैसे स्कूलों में इंद्रधनुषी झंडे लगाने, का विरोध करते हैं। इसके विपरीत, पार्टी का रुख इस्लाम के प्रति बेहद सख्त है। पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस्लाम जर्मनी का हिस्सा नहीं है और वे मस्जिदों के मीनारों तथा अजान के सार्वजनिक लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते रहे हैं। हालांकि पार्टी ईसाई धर्म की रक्षक बनती है,लेकिन जर्मनी के मुख्यधारा के चर्च, जिनमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों शामिल हैं,अक्सर एएफडी की नस्लवादी और विभाजनकारी नीतियों की सार्वजनिक रूप से निंदा करते हैं। इसके बावजूद,देश के पारंपरिक ईसाई और रूढ़िवादी मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग इस पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ है।जर्मनी की पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था के विपरीत एएफडी में कोई एक अकेला सर्वोच्च नेता नहीं है। यह पार्टी सह-नेतृत्व के मॉडल पर चलती है। वर्तमान में ऐलिस विडेल पार्टी की सबसे प्रमुख और प्रभावशाली चेहरा हैं। वे संसद में पार्टी की संसदीय समूह की नेता और राष्ट्रीय सह-अध्यक्ष हैं। एक पूर्व निवेश बैंकर होने के नाते, वे पार्टी को एक आधुनिक और आर्थिक रूप से सक्षम छवि देने का प्रयास करती हैं। उनके साथ टिनो क्रूपाल्ला पार्टी के राष्ट्रीय सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। क्रुपाल्ला मुख्य रूप से पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और पूर्वी जर्मनी के कामकाजी वर्ग के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं। प्रांतीय स्तर पर उलरिच सीगमंड का नाम बेहद तेजी से उभरा है, जिन्होंने सैक्सनी-अनहाल्ट के चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इन नेताओं के अलावा ब्योर्न होके थुरिंगिया राज्य में एएफडी के नेता हैं। इन्हें पार्टी के भीतर सबसे कट्टरपंथी और विवादित धड़े का जनक माना जाता है,और जर्मन खुफिया एजेंसियां इन्हें आधिकारिक तौर पर एक दक्षिणपंथी चरमपंथी मानती हैं।

जर्मनी के संघवाद में 16 राज्य हैं,और एएफडी की विस्तारवादी नीति देश के भीतर बेहद आक्रामक रही है। भूतपूर्व पूर्वी जर्मनी के राज्यों जैसे सैक्सनी-अनहाल्ट, थुरिंगिया,सैक्सनी और ब्रांडेनबर्ग में एएफडी इस समय सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी है। सैक्सनी-अनहाल्ट के हालिया चुनावों में पार्टी ने करीब 44 प्रतिशत वोट हासिल कर मुख्यधारा की सभी पार्टियों को पछाड़ दिया है। शुरुआत में पश्चिमी राज्यों के अमीर और उदारवादी मतदाता इस पार्टी से दूर थे,लेकिन हालिया औद्योगिक मंदी,ऊर्जा संकट और बढ़ती महंगाई के कारण पार्टी ने पश्चिमी जर्मनी के राज्यों में भी अपनी पैठ मजबूत की है। वर्तमान में,जर्मनी के 16 में से 15 राज्यों की विधानसभाओं में पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद हैं। जर्मनी की राष्ट्रीय संसद में यह मुख्य विपक्षी दलों में से एक है।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

बस किराए की मनमानी पर आरटीओ की सख्ती...यूनियन के साथ बैठक में

निर्धारित दर से अधिक वसूली पर रोक के निर्देश,हर बस में चस्पा होगी किराया सूची

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

यात्री बसों में निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूले जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने अब बस संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अंबिकापुर में बस यूनियन सरगुजा के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर निर्धारित किराया, यात्रियों से वसूली और बसों में किराया सूची प्रदर्शित करने सहित बस संचालन से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विनय सोनी ने बस संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यात्रियों से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित किराया दर के अनुसार ही राशि ली जाए। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने की शिकायत मिलने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। संचालकों को परिवहन विभाग द्वारा जारी किराया सूची भी उपलब्ध कराई गई और इसे सभी बसों में प्रमुख स्थान पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए।

किराया सूची बस में दिखाना जरूरी : बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्रियों को किराए की जानकारी के लिए बस संचालक केवल मौखिक जानकारी पर निर्भर न रहें। निर्धारित किराया सूची बस के भीतर ऐसे स्थान पर लगाई जाए, जहां यात्री उसे आसानी से देख सकें। इससे यात्री अपने गंतव्य के अनुसार निर्धारित किराया स्वयं देख सकेंगे और अधिक राशि लिए जाने की स्थिति में शिकायत भी कर सकेंगे। संलग्न BusFare2026 दस्तावेज में शासन द्वारा निर्धारित दूरीवार किराया तालिका दी गई है। इसमें दूरी के अनुसार किराए की दरें निर्धारित हैं।

शिकायत के बाद बस स्टैंड में हुई कार्रवाई

परिवहन विभाग के अनुसार हाल के दिनों में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूले जाने की शिकायतें सामने आई थीं। शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए परिवहन उड़नदस्ता द्वारा बस स्टैंड में कुछ यात्री बसों की जांच कर कार्रवाई भी की गई। इसके बाद विभाग ने बस यूनियन के साथ बैठक कर संचालकों को निर्धारित किराया व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। यह बैठक ऐसे समय हुई है,जब सितंबर की शुरुआत में भी अंबिकापुर से संचालित निजी बसों में अधिक किराया वसूले जाने की शिकायतें सामने आई थीं। मीडिया रिपोर्टों में यात्रियों की शिकायत के हवाले से अंबिकापुर-रामानुजगंज मार्ग पर करीब 115 रुपये के स्थान पर 200 रुपये तक तथा अंबिकापुर-बिलासपुर मार्ग पर करीब 230 रुपये के स्थान पर 400 रुपये तक वसूली के आरोप सामने आए थे। इन शिकायतों में कई बसों में किराया सूची प्रदर्शित नहीं होने की बात भी कही गई थी।

बस यात्रियों के लिए किराया बना बड़ा मुद्दा...

सरगुजा में बड़ी संख्या में यात्री आवागमन के लिए बसों पर निर्भर हैं। जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार अंबिकापुर आने-जाने के लिए बिलासपुर सहित विभिन्न स्थानों से बस सेवा उपलब्ध है। ऐसे में बस किराए में पारदर्शिता आम यात्रियों से सीधे जुड़ा विषय है। बसों में निर्धारित किराया सूची प्रदर्शित होने से यात्रियों को यह पता चल सकेगा कि उनके गंतव्य तक यात्रा के लिए कितना किराया देय है। इससे यात्रियों और बस कर्मचारियों के बीच किराए को लेकर होने वाले विवाद को भी कम किया जा सकता है।

यूनियन ने रखीं संचालन संबंधी समस्याएं...

बैठक में बस यूनियन के पदाधिकारियों ने भी बस संचालन में आने वाली विभिन्न समस्याओं से परिवहन अधिकारियों को अवगत कराया। संचालकों की समस्याओं पर अधिकारियों ने विस्तार से चर्चा की तथा नियमों के पालन के साथ व्यवहारिक समस्याओं के समाधान पर भी विचार किया गया। गौरतलब है कि परिवहन विभाग और बस संचालकों के बीच समन्वय को लेकर पहले भी बैठकें होती रही हैं। वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना को लेकर आयोजित जिला स्तरीय बैठक में भी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विनय सोनी,परिवहन उड़नदस्ता और बस संचालकों की मौजूदगी रही थी।

उड़नदस्ता और यातायात पुलिस की भी रहेगी नजर

मंगलवार की बैठक में परिवहन उड़नदस्ता एवं यातायात पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। विभाग की ओर से संचालकों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि शासन की निर्धारित किराया व्यवस्था का पालन करना होगा। बसों में किराया सूची चस्पा करने के साथ ही उसी के अनुरूप यात्रियों से किराया वसूलना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि बैठक के बाद सभी यात्री बसों में किराया सूची वास्तव में चस्पा होती है या नहीं और निर्धारित दर से अधिक वसूली की शिकायतों पर कितनी प्रभावी रोक लगती है।

किराए को लेकर यात्रियों की शिकायत क्या थी?

- **अंबिकापुर-रामानुजगंज:** शिकायत में करीब 115 के स्थान पर 200 तक वसूली का आरोप।
- **अंबिकापुर-बिलासपुर:** शिकायत में करीब 230 के स्थान पर 400 तक वसूली का आरोप।
- **मुख्य शिकायत:** कई बसों में किराया सूची प्रदर्शित नहीं होने से यात्रियों को निर्धारित किराए की जानकारी नहीं मिलना।

कांग्रेस नेता से मारपीट मामले में महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा

साजिशकर्ताओं के नाम एफआईआर में जोडऩे और निष्पक्ष जांच की मांग...एसपी को सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कांग्रेस मंडल अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह सिद्धू से मारपीट के मामले में अब संगठन के महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित महिला के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचीं और मारपीट की घटना में कथित रूप से शामिल साजिशकर्ताओं के नाम प्रथम सूचना में शामिल करने की मांग की। महिलाओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल, 29 अगस्त की रात मणिपुर थाना क्षेत्र के दर्रीपारा में कांग्रेस मंडल अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह सिद्धू के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। मामले की शिकायत मणिपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। घायल कांग्रेस नेता का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार कराया गया। घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मारपीट करने वाले लोगों ने कांग्रेस नेता के साथ ही घर में घुसकर महिलाओं से भी मारपीट की। वहीं घटना के पीछे एक भाजपा नेता की कथित भूमिका होने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मंगलवार को कांग्रेस नेता की पत्नी एवं पीड़िता गुरप्रीतकौर सिंह सिद्धू के साथ महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने घटना में कथित रूप से साजिश में शामिल लोगों के नाम भी एफआईआर में दर्ज करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा सोनी ने कहा कि जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। घर में घुसकर कांग्रेस नेता और महिलाओं के साथ मारपीट की घटना गंभीर है।

उन्होंने घटना के पीछे संरक्षण देने वालों की भूमिका की भी जांच की मांग की। इधर, एसपी ने महिलाओं को मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है।

एकलव्य विद्यालय की बदहाली पर पहली कार्रवाई,प्राचार्य हटाए गए...

छात्राओं के पैदल कलेक्टोरेट पहुंचने के बाद प्रशासन सख्त अधीक्षिका को नोटिस,तीन सदस्यीय जांच समिति गठित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

बतौली ब्लॉक के शिवपुर कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में लंबे समय से बनी अव्यवस्थाओं की शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। छात्राओं के करीब 30 किलोमीटर पैदल कलेक्टोरेट पहुंचने के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नाराजगी के बाद कलेक्टर अजीत वसंत ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। जांच शुरू होते ही विद्यालय के प्राचार्य को हटा दिया गया है,जबकि छात्रावास अधीक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। करीब 100 छात्राएं 7 सितंबर को विद्यालय से अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर से मिलने पैदल निकल पड़ी थीं। करीब 20 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ललित शुक्ला ने छात्राओं से मुलाकात कर उन्हें समस्याएं बताने के लिए कहा...लेकिन छात्राओं ने रास्ते में रुकने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वे कलेक्टर से मिलकर ही अपनी बात रखेंगी। इसके बाद प्रशासन ने बस की व्यवस्था कर छात्राओं को अंबिकापुर पहुंचाया। कलेक्टर के सामने छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल में करीब एक माह से बिजली की समस्या है। पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। मेस में साफ-सफाई का अभाव है। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई को लेकर भी छात्राओं ने शिकायत की।

सीएम ने लिया संज्ञान...कहा...यह स्थिति स्वीकार्य नहीं...

छात्राओं के इस तरह पैदल निकलने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि बच्चियों को अपनी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय से पैदल निकलना पड़े,यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने और लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्राचार्य बदले,अधीक्षिका से मांगा जवाब : जांच के मद्देनजर प्राचार्य ओम नारायण श्रीवास्तव को आगामी आदेश तक कार्यालय सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास अंबिकापुर में कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है। वहीं पीजीटी अंग्रेजी प्रतीक्षा त्रिपाठी को शिवपुर कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्राचार्य का दायित्व सौंपा गया है।

पीजीटी हिंदी अरविंद अशोक तिग्गा को उनके मूल पदस्थापन स्थल एकलव्य विद्यालय मैनपाट के लिए कार्यमुक्त किया गया है। छात्रावास अधीक्षिका आयुषी सोनी को शासकीय कार्य में लापरवाही और उदासीनता बरतने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। साथ ही विद्यालय के सभी अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अब कलेक्टर एवं जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद ही करने के निर्देश दिए गए हैं। तीन सदस्यीय जांच समिति अब विद्यालय में बिजली,पानी,भोजन,साफ-सफाई,शिक्षण व्यवस्था और छात्रावास प्रबंधन से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगी।

आकांक्षी विकासखंड लखनपुर में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

आकांक्षी विकासखंड लखनपुर में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जनपद पंचायत सभाकक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम कलेक्टर श्री अजीत वसंत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत श्रीमती रोमा श्रीवास्तव के मार्गदर्शन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत लखनपुर श्रीमती खुशबू शास्त्री के नेतृत्व में संपन्न हुआ। जिला पंचायत सदस्य श्री विजय अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति में साक्षरता के महत्व एवं उल्लासदूनव भारत साक्षरता कार्यक्रम के उद्देश्यों पर चर्चा की गई। शिक्षा विभाग के एबीओ श्री आलोक सिंह द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों,अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साक्षरता की शपथ दिलाई गई। साथ ही शिक्षा से वंचित एवं अक्षर ज्ञान से दूर व्यक्तियों को चिन्हांकित कर उल्लास कार्यक्रम से जोड़ने और लखनपुर की साक्षरता दर बढ़ाने हेतु सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शशिकला सिंह, उपाध्यक्ष श्री कवमेश्वर राजवाड़े,विधायक प्रतिनिधि श्री राकेश साहू, श्री विक्रम सिंह,जनपद सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं एबीपी फेलो उपस्थित रहे। इसी क्रम में विकासखंड के सभी संकुलों में भी अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया तथा जन-जन को उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की जानकारी देकर साक्षरता अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया।

स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें सरगुजा संभाग ने बताया कि संभाग स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक-पुरूष/बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरूष पद, विभिन्न संस्थाओं में सहायक ग्रेड-03 एवं सहायक ग्रेड 02 के सवंर्गीय पद एवं ए.एन.एम./ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक,महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता-महिला नर्सिंग वर्ग के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की 01 अप्रैल 2026 की स्थिति दर्शाने वाली अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। जिसका जिले की वेबसाईट www.surguja.gov.in में अवलोकन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सहायक ग्रेड-03 एवं सहायक ग्रेड 02 के सवंर्गीय पद हेतु प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर संबंधित कर्मचारी के द्वारा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कराया जाए। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक-पुरूष/बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरूष पद हेतु प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर संबंधित कर्मचारी के द्वारा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कराया जाए एवं ए.एन.एम./ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता-महिला नर्सिंग वर्ग के पद हेतु प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर संबंधित कर्मचारी के द्वारा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कराया जाए।

पुलिस डॉग 'कोका' ने सुलझाई 2 लाख की चोरी,दो आरोपी गिरफ्तार

कपड़े के निशान से संदेहियों के घर तक पहुंचा डॉग, 2.08 लाख रुपये नगद बरामद

-संवाददाता-
अंबिकापुर/दरिमा,08 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

दरिमा थाना क्षेत्र के मोतीपुर भाठापारा में दुकान से हुई करीब दो लाख रुपये की चोरी का पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से खुलासा कर दिया है। पुलिस डॉग 'कोका' घटनास्थल पर मिले कपड़े की पहचान करते हुए सीधे संदेहियों के घर तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 लाख 8 हजार 580 रुपये नगद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार मोतीपुर निवासी सुरेश महाजन 4 सितंबर को गुमला,झारखंड गए थे। 5 सितंबर को वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी दुकान में लगा डीवीआर क्षतिग्रस्त था और दुकान में रखी करीब दो लाख रुपये की रकम गायब थी। रिपोर्ट पर दरिमा थाने में अपराध क्रमांक 205/26 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने पुलिस टीम को शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी,उप पुलिस अधीक्षक राकेश बघेल तथा थाना प्रभारी दरिमा प्रशिक्षु डीएसपी निशांत गौरव कुर्रे के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

कपड़े की पहचान कर सीधे आरोपियों के घर पहुंचा 'कोका'

जांच के दौरान थाना प्रभारी एवं डॉग हैंडलर ने पुलिस डॉग 'कोका' को घटनास्थल पर ले जाकर वहां मिले कपड़े की पहचान कराई। इसके बाद 'कोका' ने रास्ता पकड़ते हुए सीधे संदेहियों के घर तक पहुंचकर पुलिस टीम को अहम सुराग दिया। इसके आधार पर पुलिस ने मोतीपुर निवासी सिद्धार्थ निषाद उर्फ रानू (25) और कबीर दास उर्फ विक्की (21) को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी पूर्व में प्रार्थी की कपड़े की दुकान में काम कर चुके हैं। सिद्धार्थ निषाद के खिलाफ पूर्व में चोरी का मामला भी दर्ज है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने दुकान में चोरी की योजना बनाकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों ने दुकान में लगे डीवीआर को तोड़कर उसके टुकड़े नदी में फेंक दिए थे,ताकि साक्ष्य मिटाया जा सके। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की पूरी रकम सहित कुल 2,08,580 रुपये नगद बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

डॉग स्क्वाड को मिलेगा पुरस्कार

मामले के खुलासे में पुलिस डॉग 'कोका' और उसके हैंडलरों आरक्षक कुलेश्वर साहू एवं नीरज वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डीआईजी एवं एसएसपी ने डॉग स्क्वाड की कार्यक्षमता की सराहना करते हुए पुलिस डॉग 'कोका' सहित टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। कार्रवाई में प्रशिक्षु डीएसपी निशांत गौरव कुर्रे,उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह,प्रशिक्षु उप निरीक्षक देव सिंह, सहायक उप निरीक्षक मनोज सिंह,आरक्षक अखलेश यादव,मकर ध्वज,सुरेश यादव, भूपेंद्र सिंह,रंजीत गुप्ता सहित थाना स्टाफ की सक्रिय भूमिका रही।

एआई से लेकर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तक, विद्यार्थियों को सिखाई उभरती तकनीक

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल और रोजगार के अवसरों से जोडऩे के उद्देश्य से मंगलवार को आईबीएम स्किलबिल्ड के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर तकनीकी सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. राजेंद्र लाकपाले ने की। मुख्य वक्ता एआई टेक्नोलॉजी ट्रेनर प्रमेय तिवारी रहे। सेमिनार में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी तकनीकों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि इन तकनीकों का उपयोग केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि औद्योगिक समस्याओं के समाधान, नवाचार और करियर निर्माण में भी किया जा सकता है। कार्यक्रम में आईबीएम स्किलबिल्ड के माध्यम से उपलब्ध तकनीकी पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण अवसरों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को वर्षभर आयोजित होने वाले लाइव तकनीकी सत्रों में भाग लेने और आईबीएम विशेषज्ञों से सीखने के अवसर की जानकारी भी दी गई। विभिन्न पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर इंडस्ट्री-रिकग्नाइज्ड डिजिटल स्किल बैज मिलने की जानकारी दी गई,जो विद्यार्थियों के तकनीकी कौशल और रोजगार क्षमता को मजबूत करने में सहायक होंगे।

दो हजार से अधिक विद्यार्थियों को दे चुके प्रशिक्षण : मुख्य वक्ता प्रमेय तिवारी ने एआई, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के व्यावहारिक उपयोगों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को उभरती तकनीकों के जरिए वास्तविक समस्याओं के समाधान और नवाचार की संभावनाओं से भी अवगत कराया। तिवारी अब तक दो हजार से अधिक विद्यार्थियों को उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रशिक्षण दे चुके हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस तरह के कौशल आधारित कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को बदलते तकनीकी दौर के अनुरूप तैयार करने और रोजगार के नए अवसरों से जोडऩे में मदद मिलेगी।

बिना अभिवहन पास खनिज परिवहन करने वाले 6 वाहनो पर हुई कार्रवाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर जिला अजीत वसंत के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 7 सितंबर 2026 को खनिज अमले द्वारा धौरपुर-लुण्ड्रा क्षेत्र एवं आसपास खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान बिना अभिवहन पास खनिजों का परिवहन करते कुल 6 वाहन पाए गए। इनमें चार टीप्पर वाहन–CG15 EF 6612,CG15 EJ 5132,CG15 EF 0357 एवं एक सोल्ड टीप्पर तथा दो हाईवा वाहन–CG15 EL 0424 एवं CG15 EF 5402 शामिल हैं।

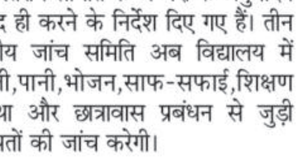

जांच में वाहन क्रमांक CG15 EF 6612 के चालक मरमानुस एवं वाहन मालिक मनोज अग्रवाल, CG15 EJ 5132 के चालक देवकुमार एवं वाहन मालिक दिलीप जायसवाल,CG15 EF 0357 के चालक पारसराम एवं वाहन मालिक दुर्गा प्रसाद गुप्ता,सोल्ड टीप्पर के चालक शुभाष एवं वाहन मालिक दीपक यादव,CG15 EL 0424 के चालक रवि यादव एवं वाहन मालिक मनोज कुमार अग्रवाल तथा CG15 EF 5402 के चालक लरग साय एवं वाहन मालिक अभिषेक श्रीवास्तव के विरुद्ध अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।

CMYK

धान की बोरी तौली गई,अब रुपयों का वजन कौन करेगा?

शिवप्रसादनगर में हमाली से 1.16 करोड़ की डेबिट तक सवाल ही सवाल

सोनपुर के 1,074 और कुर्रीडीह के 474 किसानों के लिए हमाली राशि जारी,शिवप्रसादनगर में मजदूरी,वेतन और नकद भुगतान का हिसाब सवालों में–पूर्व सत्यापन में 5,552 क्विंटल धान कम मिलने के बाद भी मदवार जांच का इंतजार

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/भैयाथान,08 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। धान खरीदी केंद्रों में किसानों और हमाल मजदूरों से जुड़ी हमाली राशि अब शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र के वित्तीय हिसाब-किताब पर एक नया सवाल खड़ा कर रही है,जिले के सोनपुर (बंजा) और कुर्रीडीह धान खरीदी केंद्रों से संबंधित दस्तावेज सामने आए हैं,जिनमें किसानों से जुड़ी हमाली राशि के भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दर्ज है,दूसरी ओर शिवप्रसादनगर के किसानों को हमाली की राशि नहीं मिलने की बात सामने आने के साथ ही समिति के बैंक खाते से हुई बड़ी निकासी और मजदूरी भुगतान की प्रविष्टियां भी सवालों के घेरे में आ गई हैं। मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि यहां सवाल केवल कुछ हजार या लाख रुपये की हमाली का नहीं,बल्कि धान खरीदी,मजदूरी,वेतन, नकद भुगतान,बैंक ट्रांसफर और स्टॉक के पूरे वित्तीय हिसाब का है, उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 12 नवंबर 2025 से 21 जुलाई 2026 तक दर्ज डेबिट प्रविष्टियों का कुल योग करीब 1.16 करोड़ बताया जा रहा है,वहीं पूर्व में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में 82.51 लाख से अधिक की डेबिट को लेकर सवाल उठाए गए थे। इन दोनों आंकड़ों को एक ही अवधि या एक ही मद का आंकड़ा मानना उचित नहीं होगा। लेकिन दोनों ही स्थितियां एक सवाल जरूर खड़ा करती हैं–आखिर समिति के खाते से निकली रकम का मदवार हिसाब क्या है?

सोनपुर में 1,074 किसानों के लिए 4.64 लाख-आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर से संबंधित उपलब्ध दस्तावेज में खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए सोनपुर (बंजा) और उपार्जन केंद्र कुर्रीडीह में धान बेचने वाले किसानों की हमाली राशि के भुगतान का उल्लेख है, दस्तावेज के अनुसार सोनपुर (बंजा) के 1,074 किसान, कुल धान 66,392.80 क्विंटल,हमाली दर 7 प्रति क्विंटल कुल राशि 4,64,749.60 किसानो के खाते जमा हुई, वहीं कुर्रीडीह में 474 किसान की कुल धान 32,361.60 क्विंटल की हमाली राशी 7 प्रति क्विंटल की दर से कुल राशि 2,26,531.20 अर्थात दोनों केंद्रों के लिए कुल 6,91,280.80 की हमाली राशि का भुगतान किया गया है,यही दस्तावेज अब शिवप्रसादनगर के किसानों के सवाल को और मजबूत करता है...जब अन्य केंद्रों में हमाली राशि के भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो शिवप्रसादनगर में किसानों की राशि कहां है?

> **एक लाख क्विंटल धान और हमाली का करीब सात लाख का गणित...**
>
> शिवप्रसादनगर केंद्र को लेकर उपलब्ध सामग्री में करीब एक लाख क्विंटल धान खरीदी का आंकड़ा सामने आया है,यदि सोनपुर के दस्तावेज में दर्ज 7 प्रति क्विंटल की दर को केवल गणितीय आधार मानें तो एक लाख क्विंटल पर हमाली राशि लगभग 7 लाख बनती है, यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सोनपुर के दस्तावेज में दर्ज 7 प्रति क्विंटल की दर को शिवप्रसादनगर पर लागू करने से पहले संबंधित वर्ष के स्वीकृत आदेश और स्थानीय व्यवस्था से सत्यापित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि शिवप्रसादनगर में भी यही दर लागू थी तो सवाल और सीधा हो जाता है–करीब एक लाख क्विंटल धान की हमाली की राशि कितनी बनी और उसका भुगतान किसे किया गया?

मजदूरों को भुगतान हुआ या किसानों की राशि उनके खाते में जानी थी?- यही वह बिंदु है जहां पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण जांच की जरूरत है,यदि संबंधित व्यवस्था के तहत हमाली की राशि किसानों को उनके खातों में दी जानी थी, तो शिवप्रसादनगर के किसानों को भुगतान क्यों नहीं हुआ? और यदि समिति ने हमाल मजदूरों को भुगतान किया,तो...कितने मजदूर थे? किसे कितना भुगतान किया गया? किस तारीख को किया गया? किस दर से किया गया? भुगतान नकद हुआ या बैंक से? मजदूरों की उपस्थिति कहां दर्ज है? इन सवालों का जवाब मजदूरी रजिस्टर,भुगतान पंजी,वाउचर और बैंक रिकॉर्ड से आसानी से निकाला जा सकता है,छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था में समितियों द्वारा व्यय की मदवार जानकारी दर्ज करने का प्रावधान है और किसानों के भुगतान के बाद उपलब्ध राशि के अन्य मदों में उपयोग तथा वास्तविक व्यय के आधार पर समायोजन की व्यवस्था भी नीति में दी गई है,इसलिए किसी भी समिति में खर्च का वास्तविक स्वरूप रिकॉर्ड से स्पष्ट होना चाहिए।

हमाली का सवाल उठा तो बैंक खाते की पुरानी कहानी भी सामने आ गई-शिवप्रसादनगर में हमाली भुगतान का सवाल उठते ही समिति के बैंक खाते की पूर्व में सामने आई प्रविष्टियां भी महत्वपूर्ण हो गई हैं,उपलब्ध स्टेटमेंट के अनुसार 12 नवंबर 2025 से 21 जुलाई 2026 तक करीब 1.16 करोड़ की डेबिट प्रविष्टियां दर्ज हैं, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सावधानी जरूरी है,इस पूरी रकम को धान खरीदी का खर्च नहीं कहा जा सकता,खाते में वेतन,मजदूरी,नकद भुगतान,बैंक शुल्क, आंतरिक ट्रांसफर और अन्य मदों की प्रविष्टियां भी शामिल हो सकती हैं,इसलिए वास्तविक सवाल है 1.16 करोड़ में धान खरीदी का खर्च कितना था और बाकी रकम किस-किस मद में गई? यही हिसाब अब सार्वजनिक होना चाहिए।

मजदूरी के नाम पर 1.59 लाख और 1.90 लाख की प्रविष्टियां-बैंक स्टेटमेंट में फरवरी 2026 की कुछ प्रविष्टियां विशेष रूप से ध्यान खींचती हैं, 4 फरवरी 2026 को 1,59,600 – 'धान खरीदी 2025-26 मजदूरी' तथा 5 फरवरी को 1,90,000– 'मजदूरी भुगतान 2025-26' के नाम से डेबिट दर्ज होने की बात सामने आई है,अब सवाल यह नहीं है कि बैंक से पैसा निकला या नहीं,सवाल यह है कि...क्या यह राशि वास्तव में मजदूरों को दी गई यदि हां तो मजदूरों की सूची सामने आए,प्रत्येक मजदूर को भुगतान की राशि सामने आए,भुगतान की तारीख और माध्यम सामने आए,मजदूरों के हस्ताक्षर अथवा बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सामने आए,और यदि यह भुगतान किसी अन्य व्यवस्था के तहत किया जाना था तो समिति के खाते से यह रकम क्यों निकाली गई–इसका भी जवाब होना चाहिए।

वेतन के नाम पर भी लाखों की निकासी-बैंक स्टेटमेंट में वेतन भुगतान से जुड़ी प्रविष्टियां भी दर्ज बताई गई हैं, 26 दिसंबर 2025 को 3.90 लाख–'जुलाई से 25 नवंबर तक वेतन' के नाम से भुगतान और 9 मार्च 2026 को 2.34 लाख–'दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक वेतन भुगतान' की प्रविष्टि का उल्लेख है,अब सवाल है कि संबंधित अवधि में समिति में कितने कर्मचारी कार्यरत थे और उनका स्वीकृत वेतन कितना था? यह भी कोई कठिन गणित नहीं है, कर्मचारियों की संख्या × मासिक वेतन × अवधि = कुल वेतन, फिर बैंक से निकली रकम से उसका मिलान किया जाए,यदि रकम बराबर है तो स्थिति साफ, यदि अंतर है तो अंतर का कारण और उसका दस्तावेज सामने आना चाहिए। **'SM SPNAGAR को भुगतान' के नाम पर नकद निकासी**- स्टेटमेंट में 'SM SPNAGAR को भुगतान किया गया' जैसे विवरण के साथ कई नकद चेक भुगतान दर्ज बताए गए हैं,फरवरी से जुलाई 2026 के बीच अलग-अलग तारीखों में 1.35 लाख, 94,360, 67,320, 1.17 लाख, 1.33 लाख,1.78 लाख, 93,280,99,076,3.90 लाख,2.96 लाख,2.70 लाख,2.88 लाख और 2.91 लाख जैसी विभिन्न राशियों की प्रविष्टियां सामने आती हैं, नकद भुगतान अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इन भुगतानों के पीछे काम क्या था? क्या उसका बिल है? क्या वाउचर है? क्या कैशबुक में प्रविष्टि है? क्या समिति का प्रस्ताव है? क्या भुगतान प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर है? यदि दस्तावेज मौजूद हैं तो भुगतान का औचित्य जांचा जा सकता है। यदि दस्तावेज नहीं हैं तो इन भुगतानों की अलग से जांच जरूरी होगी।

ट्रांसफर की रकम को भी खर्च बताना उचित नहीं-स्टेटमेंट में 'TRF AS PER TCS PRASTAV' जैसे विवरण के साथ कुछ रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर होने की जानकारी भी सामने आई है, उदाहरण के लिए 1 जनवरी 2026 को 2,06,669 और 1,44,955 की प्रविष्टियों का उल्लेख है,ऐसी रकम को सीधे धान खरीदी का खर्च मानना उचित नहीं होगा,लेकिन यहां भी तीन सवाल जरूरी हैं– ट्रांसफर किस प्रस्ताव पर हुआ? किस खाते में हुआ? उसका अंतिम उपयोग किस मद में हुआ?

और फिर सामने आया 5,552 क्विंटल धान की कमी का मामला-शिवप्रसादनगर का मामला सिर्फ बैंक खाते की डेबिट तक सीमित नहीं है, पूर्व में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार प्रशासनिक सत्यापन के दौरान शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र में 5,552 क्विंटल धान कम पाए जाने की बात सामने आई थी,रिपोर्ट में इसकी कीमत करीब 1.72 करोड़ बताई गई थी,यह तथ्य बैंक खाते की जांच से अलग है,लेकिन दोनों को एक साथ देखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक तरफ स्टॉक का सवाल है,दूसरी तरफ खाते का सवाल है, और तीसरी तरफ किसानों तथा मजदूरों के भुगतान का सवाल है, इन तीनों रिकॉर्ड का आपस में मिलान होने पर ही पूरी तस्वीर सामने आएगी।

पूर्व में खबर छपी, सवाल उठे—फिर भी जिम्मेदारों से हिसाब कौन मांगेगा?- शिवप्रसादनगर को लेकर पहले भी खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं,बैंक खाते की प्रविष्टियों पर सवाल उठ चुके हैं,धान की कमी का मामला सामने आ चुका है, अब हमाली राशि किसानों के खातों में पहुंचने की प्रक्रिया का दस्तावेज सामने आने के बाद एक नया सवाल जुड़ गया है, अगर सोनपुर और कुर्रीडीह में हमाली राशि का भुगतान किया जा सकता है,तो शिवप्रसादनगर में किसानों की राशि क्यों अटकी है? यदि मजदूरों को भुगतान कर दिया गया है तो उसका प्रमाण कहां है? यदि मजदूरों को भुगतान नहीं हुआ तो खाते से मजदूरी मद में राशि क्यों निकली? और यदि राशि किसानों के लिए थी तो उनके खातों तक क्यों नहीं पहुंची?

27 लाख के खर्च से 1.16 करोड़ की डेबिट तक—असली हिसाब कौन बताएगा?- पूर्व में उपलब्ध सामग्री में 27 प्रति क्विंटल के आधार पर करीब एक लाख क्विंटल धान पर लगभग 27 लाख का गणित सामने रखा गया था,वहीं दूसरी ओर अब उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के अनुसार संबंधित अवधि में करीब 1.16 करोड़ की कुल डेबिट प्रविष्टियां बताई जा रही हैं,इन दोनों आंकड़ों के बीच अंतर को सीधे अनियमितता कहना सही नहीं होगा, क्योंकि खाते में कई तरह के लेन-देन हो सकते हैं,लेकिन यही अंतर यह पूछने के लिए पर्याप्त है कि कुल डेबिट में धान खरीदी से जुड़े वास्तविक खर्च कितने हैं मजदूरी कितनी है? वेतन कितना है? परिवहन कितना है? नकद भुगतान कितना है? आंतरिक ट्रांसफर कितना है? और ऐसी कितनी राशि है जिसके पीछे अभी तक स्पष्ट दस्तावेज सामने नहीं आए हैं?

> **किसान पूछ रहे हैं...हमारी हमाली राशि आखिर कहां है?**
>
> किसान के लिए सवाल बहुत सीधा है, उसने धान बेचा,उसके नाम से खरीदी दर्ज हुई, हमाली की राशि निर्धारित हुई, दूसरे केंद्रों में किसानों के लिए राशि जारी होने का दस्तावेज सामने आया,तो फिर शिवप्रसादनगर के किसान क्यों इंतजार करें? और यदि यह राशि मजदूरों को दी गई है तो मजदूर भी पूछ सकते हैं–हमने काम किया, हमारा मेहनताना कितना बना और हमें कितना मिला? इसलिए यह मामला केवल समिति और किसानों के बीच का नहीं रह गया है,यह किसान, मजदूर और सहकारी समिति–तीनों के वित्तीय हिसाब की पारदर्शिता से जुड़ा सवाल बन चुका है।

> **अब सबसे जरूरी सवाल–मदवार हिसाब सार्वजनिक होगा या नहीं?**
>
> यदि समिति का पूरा खर्च नियमों के अनुसार हुआ है तो दस्तावेज सामने रखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए,मजदूरी है तो मजदूरों की सूची सामने आए,वेतन है तो कर्मचारीवार वेतन बिल सामने आए,नकद भुगतान है तो वाउचर सामने आए,ट्रांसफर है तो प्रस्ताव और उपयोगिता सामने आए, धान खरीदी का खर्च है तो स्वीकृत दर और मद सामने आए,हमाली राशि किसानों के लिए है तो किसानों के खातों में भुगतान का रिकॉर्ड सामने आए, इसके बाद सवाल अपने आप खत्म हो सकते हैं,लेकिन यदि बैंक स्टेटमेंट में बड़ी निकासी हो, दूसरी ओर किसानों की हमाली राशि लंबित हो और मजदूरी भुगतान की प्रविष्टियों का वास्तविक लाभार्थी स्पष्ट न हो,तो मदवार जांच से बचना भी सवालों को बढ़ाएगा।
>
> **धान की बोरी का हिसाब पक्का, अब रुपये–रुपये का हिसाब कौन करेगा?**
>
> किसान जब धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंचता है तो उसकी बोरी तौली जाती है,कितने क्विंटल धान आया, कितने क्विंटल खरीदा गया, कितना उठाव हुआ–हर स्तर पर रिकॉर्ड बनाया जाता है, अब वही पारदर्शिता समिति के बैंक खाते में भी दिखनी चाहिए, एक लाख क्विंटल धान का हिसाब बोरी-बोरी में लिया गया,तो खाते से निकले एक-एक रुपये का हिसाब रुपये-रुपये में क्यों नहीं? हमाली किसानों को मिली या नहीं? मजदूरों को भुगतान हुआ या नहीं? वेतन में कितना गया? नकद भुगतान किस काम में हुआ? ट्रांसफर कहां हुआ? और 12 नवंबर से 21 जुलाई तक खाते से निकली करीब 1.16 करोड़ रुपये की पूरी रकम आखिर किस-किस मद में गई? यही वे सवाल हैं जिनका जवाब अब समिति से ज्यादा संबंधित सहकारिता और प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षित है।
>
> **अंतिम सवाल-पूर्व में खबर प्रकाशित होने के बाद भी क्या कोई अधिकारी शिवप्रसादनगर के जिम्मेदारों से पूछेगा**–किसान की हमाली राशि कहां है, मजदूर का मेहनताना कहां है और समिति के खाते से निकले पैसे का पूरा हिसाब कहां है?

आरटीआई के नाम पर पहले 52 हजार का चालान, फिर 28 हजार जमा कराने के बाद भी जानकारी का इंतजार!

दरिमा बीएमओ पर सूचना अधिकार कानून की अनदेखी का आरोप,स्वास्थ्य योजनाओं के खर्च का हिसाब मांगने पर शिकायतों के जरिए दबाव बनाने का भी दावा

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,08 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरिमा के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) कार्यालय पर सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में कथित तौर पर लापरवाही बरतने का गंभीर मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष अनिल पाण्डेय ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में वित्तीय अनियमितता की आशंका को लेकर मई 2026 में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। उनका आरोप है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत शुल्क जमा करने के बावजूद अब तक मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राशि के खर्च का मांगा था पूरा ब्यौरा : पाण्डेय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वीकृत आरओपी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरिमा को उपलब्ध कराई गई राशि तथा उसके खर्च से संबंधित दस्तावेज मांगे गए थे। आरटीआई आवेदन में विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्वीकृत राशि के मदवार खर्च का विवरण,जीवन दीप समिति का बैंक स्टेटमेंट,आरओपी के विरुद्ध खर्च की गई राशि के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया तथा भुगतान से संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थीं। आवेदक का कहना है कि ये जानकारियां सीधे तौर पर सार्वजनिक धन के उपयोग और

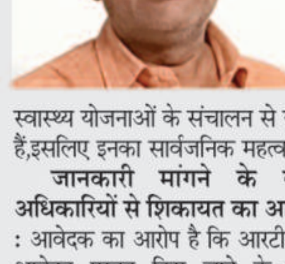

स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन से जुड़ी हैं,इसलिए इनका सार्वजनिक महत्व है।

जानकारी मांगने के बाद अधिकारियों से शिकायत का आरोप : आवेदक का आरोप है कि आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद बीएमओ डॉ. राहुल कुशवाहा द्वारा कलेक्टर सरगुजा सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके तथा संगठन के पदाधिकारियों के संबंध में शिकायतें की गईं। पाण्डेय का दावा है कि इन शिकायतों के जरिए उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया,ताकि वे मांगी गई जानकारी के मामले में आगे कार्रवाई न करें। हालांकि,आवेदक के अनुसार वे दबाव में नहीं आए और आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रखी।

पहले 52 हजार का चालान, अवलोकन के बाद 28 हजार जमा: आवेदक के मुताबिक, सूचना उपलब्ध कराने की निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के कुछ दिन पहले बीएमओ कार्यालय की ओर से पत्र जारी कर करीब 52 हजार का चालान जमा करने की जानकारी दी गई। इतनी बड़ी राशि की मांग पर आवेदक ने संपूर्ण दस्तावेजों का पहले अवलोकन करने का आग्रह किया। बताया गया कि कार्यालय द्वारा निर्धारित समय पर दस्तावेजों के अवलोकन का अवसर दिया गया। अवलोकन के दौरान आवेदक ने आवश्यक दस्तावेज चिन्हित कर उनकी प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इसके बाद कथित रूप से 28 हजार की राशि नियमानुसार जमा कराई गई।

राशि जमा होने के बाद भी जानकारी नहीं मिलने का आरोप : आवेदक का कहना है कि निर्धारित शुल्क जमा करने के बावजूद संबंधित दस्तावेज अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उनका आरोप है कि आरटीआई अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के अतिरिक्त लगभग 15 दिन और बीत जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। यही वजह है कि अब अनिल पाण्डेय ने प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सरगुजा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपील में मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ सूचना देने में कथित विलंब एवं आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है।

सवाल सार्वजनिक धन के हिसाब का है : पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राशि सरकारी स्वीकृति और आरओपी के अनुसार खर्च की गई है,तो उसके मदवार खर्च, भुगतान प्रक्रिया,बैंक स्टेटमेंट और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने में इतनी देरी क्यों हो रही है आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी किसी निजी विषय से नहीं,बल्कि सरकारी धन और स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन से जुड़ी है। ऐसे में यदि आवेदक के आरोप सही हैं तो मामला केवल एक आरटीआई आवेदन में देरी का नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। अब निगाहें प्रथम अपीलीय अधिकारी की कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या अपीलीय अधिकारी समय-सीमा के भीतर आवेदक को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश देंगे? क्या सूचना देने में हुई कथित देरी की जिम्मेदारी तय होगी? और सबसे अहम–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राशि के खर्च से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक जांच के लिए सामने आएंगे या नहीं? इन सवालों के जवाब से ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

पाइप डालो,मिट्टी भरो,GSB-WMM चढ़ाओ...धंसे तो फिर उखाड़ो!

विकास कॉरिडोर या 'कमीशन का गलियारा'? 7.18 करोड़ की सड़क में पहली बारिश ने खोल दी पोल

पहले पाइप डालो,फिर सड़क बनाओ... अब सड़क धंसी तो फिर पाइप को कंक्रीट करो!

GSB-WMM चढ़ा दिया,पाइप का बेस भूल गए? बारिश में धंसी 7.18 करोड़ की सड़क

ठेकेदार की 'शॉर्टकट टेक्नोलॉजी' या विभाग की मेहरबानी? पाइप दबा तो सड़क में बना गड्ढा

एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन,अब रीवर्क का नंबर! गंगोटी-शिवपुर सड़क में गुणवत्ता का खेल?

कल्याण गए, हेमंत आए...क्या अब सड़क का होगा सचमुच कल्याण?

5 महीने का काम 14 महीने में भी अधूरा, जो बना वह भी बैठ गया अब किसकी जिम्मेदारी?

7.18 करोड़ की गंगोटी-शिवपुर सड़क में निर्माण की 'नई तकनीक' पर सवाल,पहले कंक्रीट के बिना पाइप डालने का आरोप,अब विभाग कह रहा...उखाड़कर स्थायी बनाएंगे।

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,08 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरकारी सड़क निर्माण में तकनीक लगातार विकसित हो रही है,पहले सड़क बनती थी,फिर उसकी गुणवत्ता देखी जाती थी,लेकिन गंगोटी-शिवपुर नवापारा मार्ग पर शायद 'नई निर्माण तकनीक' का प्रयोग हो रहा है–पहले पाइप डालो, उसके ऊपर मिट्टी डालो, फिर GSB और WMM कर दो, बरसात का इंतजार करो और जब सड़क बैठ जाए तो कह दो कि अब इसे उखाड़कर पाइप को कंक्रीट से स्थायी बनाया जाएगा, यानी सड़क निर्माण का नया फार्मूला कुछ यूं नजर आ रहा है पहले निर्माण, फिर समस्या, फिर खुदाई और अंत में दोबारा निर्माण, और इस पूरी प्रक्रिया में जनता के हिस्से में क्या आया? कीचड़, गड्ढे, धंसती सड़क और सवाल।

नाम 'कल्याण',सड़क का हुआ कैसा कल्याण?- गंगोटी-शिवपुर नवापारा सड़क की देखरेख जिस अवधि में प्रभारी एसडीओ कल्याण के जिम्मे थी, उसी दौरान सड़क निर्माण की गति और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे,अब नाम में ही 'कल्याण' हो तो जनता को भी उम्मीद रहती है कि सड़क का भी कल्याण होगा,लेकिन मौके की तस्वीरें देखकर तो लगता है कि सड़क का कल्याण कुछ इस तरह हुआ कि सड़क पांच महीने में बननी थी, समय निकल गया,काम अधूरा रहा,गुणवत्ता पर सवाल उठे, और बरसात आई तो सड़क के नीचे का सच भी बाहर आ गया,अब इसे संयोग कहें,निर्माण की कमी कहें या तकनीकी चूक–इसका फैसला जांच करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि सड़क का 'कल्याण' फिलहाल जनता की परेशानी के रूप में दिखाई दे रहा है।

5 महीने का काम, 14 महीने की कहानी

लोक निर्माण विभाग के कार्यादेश के अनुसार गंगोटी से शिवपुर नवापारा तक 5.10 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है, कार्यादेश 30 जून 2025 को जारी हुआ था और कार्य अवधि 5 माह, वर्षा ऋतु सहित निर्धारित की गई थी,ठेका मे. जवाहरलाल गुप्ता को दिया गया। परियोजना की अनुमानित लागत 718.42 लाख यानी करीब 7.18 करोड़ रुपये है,अब कैलेंडर देखिए,पांच महीने कहां थे और सड़क कहां है? समय-सीमा निकल गई,लेकिन सड़क अभी भी अधूरी है,मौके पर कई हिस्सों में आवागमन की स्थिति खराब है और बारिश ने निर्माणाधीन सड़क की कमजोरियों को और उजागर कर दिया है,ऐसे में जनता का सीधा सवाल है क्या पांच महीने की परियोजना को एक्सटेंशन की ऐसी खुराक दी जा रही है कि सड़क पूरी होने से पहले ही उसकी उम्र बढ़ती रहे?

पहले खबर में अंदेशा था, अब सड़क में गड्ढा है-

निर्माण के दौरान ही सड़क की गुणवत्ता और एस्टीमेट के अनुरूप काम होने पर सवाल उठाए गए थे,तब सवाल था कि यदि सड़क के नीचे पानी की निकासी की व्यवस्था तकनीकी तरीके से नहीं की गई तो बरसात में सड़क बैठ सकती है, अब तस्वीर सामने है,सड़क के नीचे से मिट्टी हटती दिखाई दे रही है,पाइप का हिस्सा दिखाई दे रहा है। ऊपर सड़क की परत है,लेकिन नीचे खाली जगह और धंसाव जैसी स्थिति नजर आ रही है,यानी जिस बात का अंदेशा था,उसकी जमीनी तस्वीर सामने आ गई है, हालांकि केवल तस्वीर के आधार पर निर्माण दोष का अंतिम निष्कर्ष निकालना तकनीकी रूप से उचित नहीं होगा, इसके लिए विभाग को मौके की जांच, सड़क की कटिंग और पाइप के आसपास की संरचना की तकनीकी जांच करनी होगी, लेकिन सवाल यह जरूर है अगर सब कुछ तकनीकी मानकों के अनुसार था तो सड़क के नीचे यह स्थिति बनी कैसे?

ह्यूम पाइप की 'कमाल की तकनीक'- वर्क ऑर्डर में 600 मिमी व्यास के RCC NP-3/प्रेस्ट्रेस्ड पाइप कलवर्ट की 110 मीटर मात्रा दर्ज है,पाइप कलवर्ट से संबंधित बेडिंग और अन्य कार्यों का भी प्रावधान है,लेकिन मौके की तस्वीर और उपलब्ध जानकारी के अनुसार विवाद उस पाइप को लगाने के तरीके को लेकर है,आरोप है कि पाइप को पहले सीधे बिछाया गया,उसके आसपास अपेक्षित संरचनात्मक कार्य नहीं किया गया और उसके ऊपर मिट्टी,GSB तथा WMM की परतें डाल दी गईं, फिर बारिश हुई, पानी आया, मिट्टी बैठी,पाइप दबा और सड़क भी बैठ गई, अब इसे देखकर आम आदमी भी पूछ रहा है भाई,यह कौन-सी तकनीक है? पहले पाइप डालो,फिर सड़क बना दो,फिर सड़क धंसने दो,फिर सड़क उखाड़ो,फिर पाइप को कंक्रीट करो,और फिर सड़क दोबारा बनाओ, सरकारी निर्माण की यह 'रीवर्क टेक्नोलॉजी' अगर सचमुच तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है तो इसका पूरा नाम और मैनुअल भी जनता को दिखाया जाना चाहिए!

पहले अस्थायी,फिर स्थायी—तो पैसा किसका?- अब विभागीय स्तर से यह बात सामने आने की जानकारी है कि पाइप को पहले इस तरह लगाया गया था और अब संबंधित हिस्से को उखाड़कर उसे कंक्रीट कर स्थायी रूप दिया जाएगा,बस,यहीं से कहानी में नया अध्याय जुड़ता है, अगर पहले से पता था कि पाइप को स्थायी रूप से कंक्रीट करना है तो– उसके ऊपर GSB और WMM क्यों किया गया? अगर वह अस्थायी व्यवस्था थी तो उस पर सड़क की परतें क्यों डाली गईं? और यदि वह स्थायी व्यवस्था थी तो अब उसे उखाड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और सबसे महत्वपूर्ण एक ही जगह पर काम दोबारा हुआ तो उसका खर्च कौन उठाएगा? जनता का? ठेकेदार का? या फिर सरकारी रिकॉर्ड में इसे किसी दूसरी मद में समायोजित कर दिया जाएगा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परियोजना करोड़ों रुपये की है।

'पहले बनाओ, फिर सुधारो' मॉडल कितना महंगा पड़ेगा?- सड़क निर्माण में यदि किसी तकनीकी गलती को अगली लेयर डालने से पहले पकड़ लिया जाए तो सुधार अपेक्षाकृत आसान होता है,लेकिन जब उसके ऊपर सड़क की परतें बिछ जाएं और बाद में उसे उखाड़ना पड़े तो पहले का काम भी प्रभावित होता है और दोबारा निर्माण की जरूरत भी पैदा होती है, यानी जनता के लिए सड़क बनाने का उद्देश्य था एक बार खर्च करो और मजबूत सड़क बनाओ, लेकिन यदि प्रक्रिया यह बन जाए–बनाओ ? धंसाओ ? उखाड़ो ? फिर बनाओ तो सवाल केवल गुणवत्ता का नहीं, कार्य प्रबंधन और सरकारी धन की दक्षता का भी है।

GSB-WMM भी हो गया,लेकिन पाइप का बेस नहीं?- यही इस मामले का सबसे दिलचस्प पहलू है, सड़क में GSB और WMM जैसी परतों का काम आगे बढ़ चुका था,लेकिन जिस स्थान पर पानी निकासी के लिए पाइप डाला गया,वहां यदि पाइप की बेडिंग, बैकफिलिंग और कम्पेक्शन पर्याप्त नहीं था,तो ऊपर की मजबूत परतें भी कितनी देर टिकतीं? आखिर सड़क की मजबूती केवल ऊपर दिखाई देने वाली गिट्टी से तय नहीं होती, नीचे क्या है, कैसे है और कितना मजबूत है–सड़क की असली जिंदगी वहीं तय होती है, और बरसात ने शायद इसी 'नीचे' की कहानी जनता को दिखा दी।

18.18 प्रतिशत कम दर का ठेका-अब हर लेयर की जांच जरूरी- इस काम की स्वीकृति SOR से 18.18 प्रतिशत कम दर पर हुई है,कार्यादेश में निविदा राशि ?718.42 लाख और अनुबंध राशि करीब ?587.81 लाख दर्ज है,कम दर पर ठेका मिलना अपने आप में कोई अनियमितता नहीं है,लेकिन जब उसी सड़क पर समय-सीमा का सवाल हो, निर्माण की गति पर सवाल हो,गुणवत्ता पर सवाल हो,पाइप के आसपास धंसाव सामने आए, और फिर उसी हिस्से को उखाड़कर दोबारा बनाने की बात सामने आए,तो अब विभाग को तकनीकी दस्तावेजों के साथ जवाब देना चाहिए।

60 महीने की गारंटी है तो क्या 60 महीने गड्ढे भी रहेंगे?- कार्यादेश में 60 माह की परफॉर्मेंस गारंटी का प्रावधान है,यह सुनकर जनता शायद यही पूछे साहब,सड़क आज खराब हुई है, तो क्या हमें 60 महीने गारंटी की फाइल लेकर चलना होगा? गारंटी का मतलब यह नहीं कि सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता से समझौता किया जा सकता है,गारंटी तो खराबी आने पर सुधार की व्यवस्था है,लेकिन यदि निर्माणाधीन सड़क ही पहली बरसात में धंसने लगे तो प्राथमिक सवाल यह होना चाहिए कि निर्माण की प्रक्रिया में कमी कहां हुई?

अब कल्याण के बाद हेमंत एक्का की परीक्षा- अब इस सड़क की जिम्मेदारी हेमंत एक्का के एसडीओ के रूप में मिलने की जानकारी है,यानी सड़क को नया अधिकारी मिल गया,अब देखना यह है कि अधिकारी बदलने से सड़क की किस्मत भी बदलती है या सिर्फ फाइल पर नाम बदलता है,नई व्यवस्था के सामने चुनौती साफ है पाइप की तकनीकी जांच हो,धंसे हिस्से की जांच हो,सड़क की बेस और सब-बेस की गुणवत्ता जांची जाए,कम्पेक्शन टेस्ट की रिपोर्ट सामने आए,एस्टीमेट और ड्राइंग से मौके का मिलान हो,पुराने कार्य की माप और भुगतान की जांच हो,ठेकेदार को दिए गए एक्सटेंशन और नोटिस का रिकॉर्ड सार्वजनिक हो,और सबसे जरूरी–जो काम गलत हुआ है, उसे किसकी जिम्मेदारी पर दोबारा कराया जाएगा,यह स्पष्ट हो।

एक्सटेंशन का असली 'कल्याण' कौन करेगा?- अब सड़क से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य विभागीय फाइलों में छिपा है अब तक कितनी बार एक्सटेंशन दिया गया? कितने दिनों का? किस आधार पर? किस अधिकारी ने स्वीकृत किया?

ठेकेदार को कितने नोटिस दिए गए? नोटिस के बाद क्या कार्रवाई हुई? विलंब पर आर्थिक दंड लगाया गया या नहीं? अगली पूर्णता तिथि क्या है? जनता के लिए यह जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि पांच महीने की निर्धारित अवधि वाली परियोजना अब उससे कई गुना अधिक समय ले रही है।

चाय-नाश्ते की चर्चा या सड़क की गुणवत्ता की चर्चा?- क्षेत्र में अधिकारी और ठेकेदार के बीच कथित नजदीकी को लेकर भी चर्चाएं हैं, चाय-नाश्ते की चर्चा हो या कमीशन की चर्चा–इनमें से किसी को भी बिना प्रमाण तथ्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकारी सड़क में यदि गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं तो अधिकारी और ठेकेदार की बैठक में सबसे पहले चर्चा किसकी होनी चाहिए? चाय की या सड़क की? नाश्ते की या गुणवत्ता परीक्षण की? कमीशन की अफवाहों की या माप पुस्तिका की? जवाब स्पष्ट है–सड़क की गुणवत्ता की, यदि विभागीय रिकॉर्ड मजबूत है तो अफवाहों को जवाब देना भी आसान होगा।

अब 'कमीशन कॉरिडोर' शब्द क्यों चर्चा में है?- लोगों में अब इस सड़क को लेकर तरह-तरह की बातें हैं,कोई इसे विकास का कॉरिडोर कह रहा है तो कोई व्यंग्य में कमीशन का गलियारा,लेकिन पत्रकारिता की दृष्टि से किसी कमीशन लेन-देन को प्रमाण के बिना तथ्य बताना उचित नहीं होगा,हाँ,यह जरूर पूछा जा सकता है कि यदि काम समय पर नहीं हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं? यदि गुणवत्ता पर सवाल उठे तो जांच क्यों नहीं? यदि पाइप का काम दोबारा करना पड़ा तो पहली बार इसे किसने पास किया? यदि एक्सटेंशन मिला तो उसका आधार क्या था? यही सवाल इस पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने ला सकते हैं।

सड़क का 'कल्याण' अब जांच से ही होगा- गंगोटी-शिवपुर नवापारा सड़क का मामला अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां केवल ठेकेदार को दोषी बताकर या केवल विभाग को कटघरे में खड़ा करके कहानी खत्म नहीं की जा सकती,तकनीकी जांच जरूरी है, क्योंकि तस्वीरें सवाल जरूर खड़े करती हैं, लेकिन अंतिम दोष तय करने के लिए इंजीनियरिंग जांच जरूरी है,पाइप के नीचे क्या था? बेडिंग कितनी थी? बैकफिल किस सामग्री से हुआ? कम्पेक्शन कितना हुआ? पानी की निकासी की डिजाइन क्या थी? GSB और WMM की मोटाई कितनी है? धंसाव का वास्तविक कारण क्या है? और क्या मौजूदा निर्माण एस्टीमेट व स्वीकृत ड्राइंग के अनुरूप है? इन सवालों के जवाब मिलते ही पता चलेगा कि गलती ठेकेदार की थी,निगरानी की थी, डिजाइन की थी या बारिश और जल निकासी की परिस्थितियों से समस्या पैदा हुई।

अब जनता को 'सड़क' चाहिए, 'कहानी' नहीं- 7.18 करोड़ रुपये की परियोजना का उद्देश्य कोई प्रयोगशाला में नई निर्माण तकनीक आजमाना नहीं था,उद्देश्य था गंगोटी से शिवपुर नवापारा तक मजबूत और सुरक्षित सड़क देना,लेकिन आज तस्वीर यह है सड़क अधूरी है,आवागमन परेशान है, बारिश में पानी भरा है,कुछ हिस्सों में धंसाव सामने आया है,पाइप को लेकर सवाल हैं,समय-सीमा को लेकर सवाल है, एक्सटेंशन को लेकर सवाल है,और सबसे ऊपर–गुणवत्ता की निगरानी को लेकर सवाल है, अब नए प्रभारी अधिकारी हेमंत एक्का के सामने यही परीक्षा है कि वे फाइल में दर्ज सड़क देखते हैं या जमीन पर बनी सड़क,क्योंकि कागज पर सड़क कितनी भी मजबूत क्यों न हो,जनता आखिरकार उसी सड़क पर चलती है जो जमीन पर बनी होती है,और फिलहाल जमीन की तस्वीर यही पूछ रही है 5 महीने में बननी थी सड़क,14 महीने बाद भी अधूरी है, जो बना, वह पहली बारिश में बैठ गया–अब सड़क बनेगी या फिर एक्सटेंशन का ही कल्याण होता रहेगा? '

घटती-घटना
अम्बिकापुर बुधवार 02 सितम्बर 2026
विकास कॉरिडोर या कमीशन का गलियारा?
7.18 करोड़ की सड़क पहली बारिश में ही धंसी!
7.18 करोड़ की सड़क में धंसा रास्ता,ह्यूम पाइप के आसपास मिट्टी गायब-कौन देगा जवाब?

झारखंड के बूचड़खाने ले जाए जा रहे 7 मवेशी बरामद,दो तस्कर गिरफ्तार

कुसमी पुलिस की कार्रवाई में स्थायी वारंटी भी पकड़ाया...मारते-पीटते पैदल ले जा रहे थे मवेशियों को...

-संवाददाता-

कुसमी/बलरामपुर 08 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

मवेशियों की अवैध तस्करी के खिलाफ कुसमी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 मवेशियों को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया,जिनमें से एक आरोपी पुलिस के अनुसार लंबे समय से फरार स्थायी वारंटी भी है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार घटना 7 सितंबर 2026 की है। कुसमी पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम कटिमा के ढोंग सरना के पास कुछ लोग मवेशियों को कथित रूप से मारते-पीटते और क्रूरतापूर्वक हांकते हुए झारखंड की ओर ले जा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।

घेराबंदी कर 7 मवेशियों समेत दो को पकड़ा : पुलिस टीम ने मौके पर संदिग्ध गतिविधि में शामिल दो लोगों को पकड़ लिया। उनके कब्जे/साथ से 7 नग मवेशी–गाय, बैल एवं बछड़े बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने कथित रूप से इन मवेशियों को झारखंड स्थित बूचड़खाने ले जाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने सभी मवेशियों को जब्त कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

एक आरोपी निकला स्थायी वारंटी : गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अज्मेरूल्ला अंसारी (34), निवासी ग्राम खमली, थाना आस्ता, जिला जशपुर तथा जितेन्द्र राम बुनकर (29), निवासी ग्राम खमली, थाना आस्ता,जिला जशपुर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक अज्मेरूल्ला अंसारी के विरुद्ध पूर्व से न्यायालय की कार्रवाई लंबित थी और वह स्थायी वारंटी था। मवेशी तस्करी के मामले में गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने उसे पुराने वारंट के मामले में भी गिरफ्तार किया है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ अपराध : कुसमी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 79/2026 दर्ज किया है। मामले में छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 एवं 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(घ) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

तस्करी के नेटवर्क पर भी उठे सवाल : कुसमी क्षेत्र झारखंड की सीमा से जुड़ा होने के कारण मवेशियों की आवाजाही और कथित तस्करी पर लगातार निगरानी की आवश्यकता बनी रहती है। इस कार्रवाई में सात मवेशियों को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि,इस मामले में एक बड़ा सवाल यह भी है कि मवेशियों को झारखंड ले जाने के पीछे क्या कोई बड़ा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है? गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में यदि अन्य लोगों, वाहन चालकों, खरीदारों अथवा बूचड़खाने से जुड़े नेटवर्क की जानकारी सामने आती है तो पुलिस की कार्रवाई और आगे बढ़ सकती है। फिलहाल कुसमी पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और बरामद मवेशियों को सुरक्षित कर दिया गया है।

करोड़ों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहली बरसात भी नहीं झेल पाया टपकने लगा छत

खड़गवां के नव निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की गुणवत्ता पर बड़े सवाल,पहली बारिश ने खोली निर्माण की पोल?

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन लोकार्पण से ही पहले ही छत में हुआ जगह जगह बैरिंग कोट दीवारे भी जगह जगह पर मरम्मत होने लगा कितनी अच्छी है गुणवत्ता?

-राजेन्द्र शर्मा-
खड़गवां,08 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

खड़गवां स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से खड़गवां विकासखंड में करोड़ों रुपये की लागत से नव निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने को है, लेकिन भवन के लोकार्पण से पहले ही इसकी गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। पहली ही बरसात में भवन की छत से जगह-जगह पानी टपकने की बात सामने आई है, जिसके बाद निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि छत से पानी रिसने की समस्या सामने आने के बाद लोकार्पण से पहले ही ठेकेदार द्वारा छत पर बैरिग कोट कर मरम्मत कार्य कराया गया है जो छत पर कार्य का होना स्पष्ट दिखाई दे रहा है,सवाल यह है कि करोड़ों रुपये की लागत से तैयार हो रहा नया भवन यदि निर्माण पूरा होने और लोकार्पण से पहले ही पानी टपकाने लगे,तो आने वाले वर्षों में इसकी स्थिति क्या होगी ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है?

पहली बारिश में ही भवन पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक धन से निर्मित इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य भवन में गुणवत्ता के मानकों का कड़ाई से पालन होना चाहिए था,लेकिन पहली ही बरसात में कथित रूप से छत से पानी रिसने की शिकायतों ने निर्माण एजेंसी और गुणवत्ता निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं,'जब लोकार्पण से पहले यह हाल है, तो लोकार्पण के बाद भवन की दशा क्या होगी?' यह सवाल अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है।

कम दर के ठेके और गुणवत्ता पर सवाल-

आरोप है कि कई ठेकेदार कम दर पर ठेका प्राप्त करने के बाद लागत बचाने के लिए निर्माण गुणवत्ता से समझौता करते हैं, खड़गवां के इस महत्वपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को लेकर भी इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, सूत्रों से जानकारी मिली थी कुछ श्रमिकों और मिस्त्रियों के द्वारा भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर आपत्ति जताने की चर्चा भी सामने आई थी,आरोप है कि गुणवत्ता संबंधी सवाल उठाने वाले कुछ श्रमिकों और मिस्त्रियों को बाद में काम से अलग कर दिया गया था?

पहले हुई बहुत प्रशंसा, अब खुल रही पोल?- इस नव निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य को लेकर पूर्व में कुछ समाचारों में गुणवत्ता की प्रशंसा भी की गई थी, लेकिन अब बारिश के दौरान छत से पानी टपकने की शिकायतों ने उन दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है? जिस भवन को क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक बड़ी सौगात और स्वास्थ्य मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा था उसी भवन की गुणवत्ता पर लोकार्पण से पहले सवाल उठना चिंता का विषय है, आवश्यकता है जाच कि लोकार्पण से पहले ही तकनीकी विशेषज्ञों की स्वतंत्र टीम द्वारा भवन की गुणवत्ता,छत की वाटरप्रूफिंग, उपयोग की गई निर्माण सामग्री और पूरे निर्माण कार्य की जांच कराई जाए। यदि कहीं निर्माण में लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता पाया जाता है तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, करोड़ों खर्च होने के बाद भी यदि नया अस्पताल पहली बारिश नहीं झेल पाया, तो क्या मरीजों के लिए बनने वाला यह भवन आने वाले वर्षों में सुरक्षित और टिकाऊ साबित होगा? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य में सी जी एम एस सी के अधिकारियों की लापरवाही और बिना देखरेख के और ठेकेदार की सांठगांठ के कारण ये करोड़ों की लागत का भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया इस निर्माण कार्य के संबंध में सी जी एम एस सी के एस डी ओ को गुणवत्ता के संबंध मे कहा गया था तो उन्होंने जवाब दिया था हम भवन बनाते हैं यही भवन सी जी एम एस सी के एस डी ओ और इंजिनियर ने बनाया है जो लोकार्पण से पहले ही मरम्मत किया जा रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपने गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य की पोल खोल रहा है? लोकार्पण से पहले ही टपकती छत ने करोड़ों के निर्माण पर सवालों की बारिश कर दी है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग गुणवत्ता की वास्तविक जांच करता है या फिर केवल मरम्मत की परत चढ़ाकर मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है,इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के गुणवत्ता के संबंध में दूरभाष से संपर्क भवन की जानकारी ली तो एस डी ओ संतोष सोनी ने कहा की लोकार्पण से पहले हम मरम्मत कर लोकार्पण करायेंगे?

सीजीएमएससी एसडीओ संतोष सोनी

अब सवाल यह है कि जब भवन लोकार्पण से पहले मरम्मत कार्य होगा तो आगे करोड़ों रुपए के भवन की गुणवत्ता क्या होगी या हर वर्ष भवन का सिर्फ मरम्मत के लिए लाखों रूपए जनता के टैक्स के पैसों को बरबाद किया जाएगा? नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की गुणवत्ता विहीन निर्माण के लिए एमसीबी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि भवन जगह जगह टपक रहा है दीवारों में दरारें आ रही है इस की गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की शुरुआत में ही शिकायत की गई थी मगर किसी प्रकार कि कोई कार्यवाही नहीं हुई निर्माण स्थल पर किसी प्रकार का कोई सूचना पटल भी नहीं लगाया गया की भवन की क्या लागत है उन्होंने ने कहा कि क्षेत्र में जितने भी निर्माण कार्य किए जा रहे सभी घटिया और गुणवत्ता विहीन निर्माण है चाहे भवन सड़क पुल पुलिया आदि सभी घटिया और गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव

शिक्षक दिवस पर संकुल स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, उत्कृष्ट शिक्षकों का हुआ सम्मान

पदोन्नति एवं स्थानांतरण पर शिक्षकों को दी गई ससम्मान विदाई,नवपदस्थ शिक्षकों का आत्मीय स्वागत

-संवाददाता-
सूरजपुर,08 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

शिक्षक दिवस के अवसर पर संकुल केंद्र कोट, विकासखंड रामानुजनगर में संकुल स्तरीय शिक्षक सम्मान सह विदाई समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया,कार्यक्रम में संकुल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया, वहीं पदोन्नति एवं स्थानांतरण के बाद नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे शिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर ससम्मान विदाई दी गई तथा संकुल में नवपदस्थ शिक्षकों का आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संकुल प्राचार्य महेश कुमार दोहरे रहे, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधान पाठक माध्यमिक शाला चिटकाहीपारा-कोट अशोक उपाध्याय एवं प्रधान पाठक माध्यमिक शाला पंपापुर दिनेश द्विवेदी उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत मां सरस्वती एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई, छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम को आध्यात्मिक एवं गरिमामय स्वरूप प्रदान किया।

उत्कृष्ट कार्य के लिए तीन शिक्षकों का सम्मान-समारोह के दौरान संकुल अंतर्गत सत्र 2025 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान प्रदान किया गया,सम्मानित शिक्षकों में प्राथमिक शाला भदरापारा के सहायक शिक्षक नंदलाल सिंह,पूर्व माध्यमिक शाला चिटकाहीपारा-कोट के शिक्षक सुरेन्द्र राजवाड़े तथा शासकीय हाई स्कूल कोट के व्याख्याता कमल किशोर पाण्डेय शामिल रहे,शिक्षकों के सम्मान से समारोह में उपस्थित शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला,उपस्थित लोगों ने सम्मानित शिक्षकों के कार्यों की सराहना करते हुए इसे अन्य शिक्षकों के लिए भी प्रेरणादायक बताया।

पदोन्नति और स्थानांतरण पर भावभीनी विदाई-कार्यक्रम में संकुल केंद्र कोट के जनशिक्षक शिवलाल सिंह के माध्यमिक शाला रामपुर में प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नत होने तथा माध्यमिक शाला कोट के प्रधान पाठक बाबुलाल साहू का माध्यमिक शाला बरहोल में स्थानांतरण होने पर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर ससम्मान विदाई दी गई,वहीं संकुल केंद्र कोट में सहायक शिक्षक श्रीमती शालिनी साहू एवं धर्मेन्द्र दुबे की नवीन पदस्थापना होने पर उनका स्वागत किया गया, शिक्षकों ने एक-दूसरे के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए नई जिम्मेदारियों में बेहतर कार्य करने की कामना की।

शिक्षक बच्चों के भविष्य के निर्माता : महेश कुमार दोहरे-मुख्य अतिथि एवं संकुल प्राचार्य महेश कुमार दोहरे ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक बच्चों के भविष्य के निर्माता होते हैं,माता-पिता बच्चों को जन्म देते हैं,लेकिन शिक्षक उन्हें शिक्षा प्रदान कर उनके जीवन को संवारने के साथ जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं,उन्होंने कहा कि शिक्षक के आचरण का सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। शिक्षक जैसा व्यवहार करते हैं,बच्चे भी उसी से सीखते हैं,इसलिए प्रत्येक शिक्षक को अच्छे आचरण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करना चाहिए, उन्होंने शिक्षा में नवाचार को अपनाने तथा विद्यार्थियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर-प्रधान पाठक अशोक उपाध्याय ने शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन हो रहा है,ऐसे में शिक्षकों को स्वयं को लगातार अपडेट करते हुए विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए, उन्होंने शिक्षकीय मर्यादा का पालन करते हुए अपने दायित्वों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करने पर जोर दिया, प्रधान पाठक दिनेश द्विवेदी ने शिक्षक दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन एवं व्यक्तित्व की चर्चा की, उन्होंने शिक्षकों से उनके आदर्शों और बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया।

न्योता भोज ने बढ़ाई आत्मीयता-समारोह के दौरान संयुक्त विद्यालय परिवार की ओर से आयोजित स्वादिष्ट न्योता भोज ने कार्यक्रम को और अधिक आत्मीय बना दिया, शिक्षक-शिक्षिकाओं, विद्यार्थियों एवं उपस्थित अतिथियों ने सामूहिक रूप से भोजन किया, इससे समारोह में आपसी सौहार्द और विद्यालय परिवार की एकजुटता का भाव देखने को मिला, कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता चांसी प्रसाद कुशवाहा ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन शिक्षक राधेश्याम साहू ने किया,इस अवसर पर संकुल प्राचार्य महेश कुमार दोहरे, प्राचार्य उमापुर चन्द्र प्रताप साहू,प्रधान पाठक अशोक उपाध्याय, दिनेश द्विवेदी,फूल सिंह,नागेन्द्र यादव, उर्मिला रवि, अल्ताफ अली,निर्मल प्रसाद, बाबुलाल साहू, राधेश्याम साहू,संकुल समन्वयक बरहोल रामकृपाल साहू, पूर्व संकुल समन्वयक शिवलाल सिंह,कमल किशोर पाण्डेय,चांसी प्रसाद कुशवाहा,यदुवंश नारायण साहू,अनुरंजन टोप्पो, तारकेश सिंह,केशरी राजवाड़े,अनिता साहू,खेलसाय पोर्ते,उमाशंकर साहू, रोहित साहू,लक्ष्मी ठाकुर,नंदलाल सिंह,शालिनी साहू, धर्मेन्द्र दुबे,वीरेन्द्र सिंह,सुशीला,सुखमनिया, हिरामनी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बच्चे उपस्थित रहे।

ढाई साल से उधार के भवन में तहसील कार्यालय,स्थायी भवन का इंतजार

कांग्रेस नेता राजीव गुप्ता ने फेसबुक पोस्ट के जरिए उठाया सवाल,पुराने प्रशासनिक परिसर की जमीन पर संयुक्त भवन बनाने का दिया सुझाव

-संवाददाता-
बैकुण्ठपुर,08 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर में आम जनता और किसानों से सीधे जुड़े तहसील कार्यालय की स्थिति इन दिनों प्रशासनिक व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े कर रही है, पुराने भवन के जर्जर हो जाने के बाद तहसील कार्यालय को पिछले करीब ढाई वर्षों से बस स्टैंड स्थित वन विभाग के डिपो परिसर के सामुदायिक भवन 'आस्था भवन' में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संचालित किया जा रहा है,अस्थायी तौर पर शुरू की गई यह व्यवस्था अब लंबे समय से चल रही है, लेकिन तहसील कार्यालय के लिए स्थायी भवन कब और कहां बनेगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

तहसील कार्यालय ऐसा प्रशासनिक केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण और आम नागरिक राजस्व संबंधी कार्यों के लिए पहुंचते हैं,नामांतरण,बंटवारा, सीमांकन,भूमि संबंधी मामलों सहित विभिन्न कार्यों के लिए लोगों को तहसील कार्यालय जाना पड़ता है,ऐसे महत्वपूर्ण कार्यालय का वर्षों तक जर्जर भवन में और उसके बाद वैकल्पिक भवन में संचालन होना अब चर्चा का विषय बन गया है।

जनता के दबाव के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन?-इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राजीव गुप्ता ने अपने फेसबुक हैंडल पर पोस्ट करते हुए व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं,उन्होंने लिखा कि जिला मुख्यालय का तहसील कार्यालय पिछले ढाई वर्षों से उधार के भवन में संचालित हो रहा है,लेकिन इस महत्वपूर्ण कार्यालय के लिए स्थायी व्यवस्था को लेकर न तो जवाबदेह जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई सार्थक पहल दिखाई दी और न ही प्रशासनिक स्तर पर ऐसी पहल नजर आई,जिससे शहरवासियों को स्थायी समाधान की उम्मीद बंधे,गुप्ता ने अपने पोस्ट में सवाल उठाते हुए कहा कि यह मामला केवल तहसील कार्यालय के भवन का नहीं है,बल्कि इससे यह भी सामने आता है कि जनता की बुनियादी जरूरतों को लेकर जिम्मेदार लोग कितने जागरूक और कितने उदासीन हैं,उन्होंने व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता की सेवा,संपूर्ण विकास और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं,लेकिन जमीनी स्तर पर कई बुनियादी समस्याओं की पहचान और उनका समाधान तब तक होता दिखाई नहीं देता, जब तक जनता की ओर से आवाज नहीं उठाई जाती।

पुरानी सरकारी जमीन के उपयोग का दिया सुझाव-

कांग्रेस नेता राजीव गुप्ता ने अपनी पोस्ट में इस समस्या के स्थायी समाधान के साथ-साथ बैकुण्ठपुर की पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को पुनर्गठित करने का सुझाव भी दिया है, उन्होंने कहा कि पुराने तहसील कार्यालय से लेकर पुराने एसपी, एसडीएम तथा खेल एवं युवा कल्याण कार्यालय तक उपलब्ध सरकारी भूमि का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए, उपलब्ध जमीन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर कार्यालय की तर्ज पर यहां एक बहुउद्देशीय संयुक्त प्रशासनिक भवन विकसित करने की योजना बनाई जा सकती है, उनके मुताबिक, यह काम चरणबद्ध तरीके से भी किया जा सकता है। वर्तमान में उपलब्ध भूमि पर पहले जरूरी कार्यालयों का निर्माण किया जाए और भविष्य में एसपी कार्यालय के नए भवन में स्थानांतरित होने के बाद उपलब्ध होने वाली जमीन का दूसरे चरण में उपयोग किया जा सकता है।

एक परिसर में हों कई महत्वपूर्ण कार्यालय- गुप्ता ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित संयुक्त प्रशासनिक परिसर में केवल तहसील कार्यालय ही नहीं, बल्कि एसडीएम कार्यालय,रोजगार कार्यालय, आरआई एवं पटवारी कार्यालय सहित अन्य ऐसे सरकारी कार्यालयों को भी शामिल किया जाए, जो वर्तमान में जर्जर,किराये या वैकल्पिक भवनों में संचालित हो रहे हैं, उन्होंने यह भी कहा कि मनेंद्रगढ़ में संचालित कोरिया जिले के जिला स्तरीय कार्यालयों को भी आवश्यकता और प्रशासनिक दृष्टि से एक ही परिसर में लाने की योजना पर विचार किया जा सकता है,यदि ऐसा प्रशासनिक परिसर विकसित होता है तो आम नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है,राजस्व और प्रशासन से जुड़े कई कार्य एक ही क्षेत्र में होने के कारण किसानों,ग्रामीणों और आम नागरिकों का समय एवं संसाधन बच सकता है, वहीं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच समन्वय भी बेहतर हो सकता है।

पुरानी सिविल लाइन को फिर मिल सकती है प्रशासनिक पहचान-राजीव गुप्ता ने अपनी पोस्ट में बैकुण्ठपुर की पुरानी सिविल लाइन के पुराने स्वरूप को भी चर्चा में लाया है,उनका कहना है कि शहर के बाहर कोर्ट,एसपी कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय चले जाने के कारण पुरानी सिविल लाइन क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियां कम हुई हैं,इसका असर आसपास की व्यापारिक गतिविधियों पर भी पड़ा है,ऐसे में यदि पुराने प्रशासनिक क्षेत्र में एक संयुक्त प्रशासनिक परिसर विकसित किया जाता है तो यह इलाका फिर से प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बन सकता है,रोजाना बड़ी संख्या में आम लोगों,अधिकारियों,कर्मचारियों और अन्य लोगों की आवाजाही होने से आसपास के व्यापार को भी गति मिलने की संभावना है।

सवाल स्थायी समाधान का-बैकुण्ठपुर में तहसील कार्यालय के लिए वैकल्पिक भवन की व्यवस्था किए करीब ढाई वर्ष बीत चुके हैं,ऐसे में अब सवाल यह है कि अस्थायी व्यवस्था आखिर कब तक जारी रहेगी और स्थायी भवन के लिए ठोस प्रक्रिया कब शुरू होगी,शहरवासियों के सामने दो विकल्प दिखाई देते हैं–या तो तहसील कार्यालय के लिए अलग से आधुनिक और सुविधायुक्त भवन तैयार किया जाए अथवा उपलब्ध सरकारी जमीन का बेहतर उपयोग करते हुए तहसील समेत अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों को एक ही परिसर में लाने की दीर्घकालीन योजना बनाई जाए, संयुक्त प्रशासनिक भवन का सुझाव केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है,यदि इसे योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाता है तो इससे जनता को एक स्थान पर कई प्रशासनिक सुविधाएं, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और शहर के पुराने प्रशासनिक क्षेत्र को नई पहचान मिल सकती है,फिलहाल तहसील कार्यालय 'आस्था भवन' में वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे चल रहा है और स्थायी भवन की जरूरत बरकरार है,कांग्रेस नेता राजीव गुप्ता की फेसबुक पोस्ट ने इस मुद्दे को सार्वजनिक चर्चा में ला दिया है,अब देखना होगा कि प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस सुझाव को केवल राजनीतिक बयान के रूप में देखते हैं या बैकुण्ठपुर की दीर्घकालीन प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कोई ठोस पहल करते हैं।

स्ट्रोक के लक्षण पहचानें,समय पर उपचार लें : फिजियोथेरेपिस्ट

विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर सियान गुड़ी सेंटर में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम,वरिष्ठजनों ने खेल और मनोरंजक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर अनामिका वेलफेयर सोसायटी के सौजन्य से सियान गुड़ी सेंटर,अंबिकापुर में स्वास्थ्य जागरूकता,खेल एवं मनोरंजक गतिविधियों से भरपूर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय 'सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट एवं स्ट्रोक की रोकथाम, प्रबंधन और पुनर्वास' रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठजनों एवं आम नागरिकों को स्ट्रोक के कारणों,शुरुआती लक्षणों,बचाव, समय पर उपचार तथा पुनर्वास के प्रति जागरूक करना था। विशेषज्ञों ने नियमित शारीरिक गतिविधि, संतुलित जीवनशैली और फिजियोथेरेपी को स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. जय शंकर

चौधरी, डॉ. खुशबू एवं डॉ. श्रुति ने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव और फिजियोथेरेपी की उपयोगिता के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने स्ट्रोक के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज नहीं करने तथा लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही स्ट्रोक के बाद मरीज की शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाने में फिजियोथेरेपी एवं पुनर्वास की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया।

खेलों में दिखा वरिष्ठजनों का उत्साह : स्वास्थ्य जागरूकता के साथ कार्यक्रम में वरिष्ठजनों के लिए विभिन्न खेल एवं मनोरंजक गतिविधियां भी आयोजित की गईं। उम्र के इस पड़ाव में भी वरिष्ठजनों का उत्साह देखते ही बना। उन्होंने पूरे जोश के साथ विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार इन गतिविधियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि वरिष्ठजनों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के साथ मानसिक प्रसन्नता, आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देना भी था।

कविताओं से बांधा समां : कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठजन श्री बी.डी. लाल एवं श्री लाल मालवीय ने प्रेरणादायक कविताओं की प्रस्तुति दी। उनकी कविताओं के माध्यम से सकारात्मक सोच रखने, सक्रिय जीवन जीने तथा उम्र के इस पड़ाव में भी उत्साह और आत्मविश्वास बनाए रखने का संदेश दिया गया। उनकी प्रस्तुति को उपस्थित लोगों ने सराहा। कार्यक्रम का संचालन सुश्री रीता अग्रवाल ने किया। उन्होंने अतिथियों एवं वरिष्ठजनों का स्वागत करते हुए विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की निवेदक श्रीमती जानकी सिंह ने अतिथियों, विशेषज्ञों, वरिष्ठजनों एवं सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य की देखभाल में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। अंत में सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। अनामिका वेलफेयर सोसायटी की यह पहल वरिष्ठजनों को स्वस्थ,सक्रिय एवं आत्मविश्वासपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करने के साथ स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में सार्थक प्रयास रही।

प्यार,विश्वासघात की कहानी लेकर आ रही लव लॉटरी

असली रिश्तों की पहचान कराएगी फिल्म

अक्षय ओबेरॉय की सस्पेंस थ्रिलर लव लॉटरी का ट्रेलर जारी हो गया है,जो आधुनिक रिश्तों,शादी और विश्वासघात के कानूनी दांव-पेंच को दर्शाती है।
अपकमिंग हिंदी सस्पेंस थ्रिलर और सोशल कोर्टरूम ड्रामा फिल्म लव लॉटरी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में फिल्म के मुख्य कलाकार अक्षय ओबेरॉय, विजयंत कोहली और अग्नि अग्यारी, निर्देशक अरविंद पांडे और निर्माता कुलदीप भार्गव (तुषार) मौजूद रहे।
कई ऐसे परिवार भी इस लॉन्च में शामिल हुए जिन्होंने महिला-केंद्रित कानूनों के दुरुपयोग का व्यक्तिगत रूप से सामना किया है।

पता करेगी रिश्ते की असलियत

सिनेमा-गंज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म लव लॉटरी मार्डन रिलेशनशिप, शादी,विश्वासघात और उससे जुड़े कानूनी विवादों पर गहराई से प्रकाश डालती है। इसके साथ ही ये पुरुषों के अधिकारों के मुद्दे को भी नाटकीय अंदाज में पेश करती है।
2 मिनट 10 सेकंड का ट्रेलर तुरंत ही एक ऐसी दुनिया में आपको ले जाएगा जहां प्यार हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। आधुनिक रिश्तों की चमक-दमक के पीछे अविश्वास, छल और भावनात्मक संघर्ष छिपे होते हैं।

जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, शादी,तलाक,विश्वासघात और पैसों के लालच में की गई शादियां के प्लॉट सामने आते हैं।

कौन से कलाकार आएंगे नजर?

अक्षय ओबेरॉय इस फिल्म के मुख्य कलाकार के तौर पर नजर आएंगे। फिल्म की कहानी प्यार, विश्वास, संदेह और न्याय की लड़ाई के इर्द-गिर्द घूमती है। हेली दारूवाला और अन्य सपोर्टिंग एक्टर्स मूवी में कई परतें जोड़ेंगे। ट्रेलर दर्शकों के मन में सवाल छोड़ता है कि आखिर रिश्ते के अंदर क्या हुआ? कौन सच बोल रहा है? कौन सही है और कौन गलत? आपको अंत तक कुछ भी समझ नहीं आएगा।

करीना कपूर खान और संजय लीला भंसाली की मुलाकात से बढ़ी हलचल

बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान और मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की हालिया मुलाकात ने फिल्म इंडस्ट्री में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है।
करीना कपूर मंगलवार (8 सितंबर) को मुंबई में संजय लीला भंसाली के ऑफिस पहुंचीं, जिसके बाद दोनों के बीच किसी संभावित प्रोजेक्ट को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं।समय और कैलेंडर करीना को भंसाली के ऑफिस जाते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अभिनेत्री हल्के नीले रंग के सूट में नजर आ रही हैं। वीडियो में वह बिना रुके सीधे फिल्ममेकर के ऑफिस की ओर जाती दिखाई दे रही हैं। हालांकि, उन्होंने वहां मौजूद पैपराजी के लिए पोज नहीं दिया।
करीना के इस दौरे ने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का ध्यान इसलिए भी खींचा है क्योंकि लंबे समय बाद दोनों के साथ आने की संभावना जताई जा रही है।

देवदास' के बाद पहली बार साथ आने की चर्चा

संजय लीला भंसाली और करीना कपूर खान के बीच करीब 25 साल पहले फिल्म 'देवदास' को लेकर चर्चा हुई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच कुछ मतभेद हो गए थे। 'देवदास' साल 2002 में रिलीज हुई थी और इसमें शाहरुख खान,ऐश्वर्या राय बच्चन और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म को भारतीय सिनेमा की चर्चित फिल्मों में गिना जाता है। बताया जाता है कि करीना कपूर भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी थीं, लेकिन बाद में फिल्म की कास्टिंग को लेकर बदलाव हुए। इसके बाद दोनों के बीच दूरी की खबरें सामने आई थीं। हालांकि, अब इतने वर्षों बाद करीना का भंसाली के ऑफिस जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि दोनों के बीच पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नए प्रोजेक्ट पर बातचीत हो सकती है।

नई फिल्म में फीमेल लीड को लेकर चर्चा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय लीला भंसाली अपनी आने वाली फिल्म के लिए करीना कपूर खान से संपर्क कर सकते हैं। इस फिल्म में तमिल अभिनेता धनुष के होने की भी चर्चा है। हालांकि,अभी तक फिल्म या कास्टिंग को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन करीना और भंसाली की मुलाकात के बाद इंडस्ट्री में इस संभावित सहयोग को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। अगर करीना इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती हैं तो यह पहली बार होगा जब वह संजय लीला भंसाली के निर्देशन में किसी फिल्म में नजर आएंगी।

करीना का शानदार फिल्मी सफर

करीना कपूर खान बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में फिल्म 'रिफ्यूजी' से की थी। इसके बाद उन्होंने 'कभी खुशी कभी गम', 'जब वी मेट', 'ओमकारा', '3 इडियट्स', 'तलाश' और कई अन्य फिल्मों में शानदार अभिनय किया। करीना अपने किरदारों में विविधता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने रोमांटिक,कॉमेडी, ड्रामा और गंभीर भूमिकाओं में अपनी अलग पहचान बनाई है। हाल के वर्षों में भी करीना लगातार फिल्मों और वेब प्रोजेक्ट्स में सक्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता आज भी दर्शकों के बीच कायम है।

भंसाली की फिल्मों की खास पहचान

संजय लीला भंसाली भारतीय सिनेमा के उन निर्देशकों में शामिल हैं, जिनकी फिल्मों में भव्यता, संगीत और मजबूत कहानी देखने को मिलती है। 'हम दिल दे चुके सनम', 'देवदास','गोलियों की रासलीला राम-लीला', 'बाजीराव मस्तानी' और 'पद्मावत' जैसी फिल्मों ने उन्हें अलग पहचान दिलाई है। भंसाली अपनी फिल्मों में कलाकारों के चयन को लेकर काफी सावधानी बरतते हैं। उनके साथ काम करना कई कलाकारों के लिए करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है।

रवि मोहन की फिल्म एन ऑर्डिनरी मैन से जुड़ी केनीशा

रवि मोहन के साथ कथित रिश्ते को लेकर आलोचनाओं के बाद सोशल मीडिया छोड़ने का फ़ैसला करने के कुछ महीनों बाद,केनीशा फ्रांसिस रवि मोहन की पहली डायरेक्टोरियल फ़िल्म एन ऑर्डिनरी मैन में कंपोज़र के तौर पर शामिल हो गई हैं। रवि मोहन स्टूडियोज़ ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए एन ऑर्डिनरी मैन में केनीशा के शामिल होने की घोषणा की।

पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, एक नई आवाज़ आई है। एक नया अध्याय। वही रूह। एक ऐसी आर्टिस्ट जिसे आप जानते हैं,लेकिन जिसका संगीत आपने पहले कभी नहीं सुना। एन ऑर्डिनरी मैन एक नई आवाज़। एक शानदार डेब्यू। सिनेमा का स्वागत करता है।
केनीशा ने भी एक और पोस्ट में अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा,आरएम आपने मुझ पर जो भरोसा और ईमानदारी दिखाई है, उसके लिए मैं वादा करती हूँ कि अपना सर्वश्रेष्ठ दूँगी। इस मौके के लिए धन्यवाद। आशीर्वाद। आपकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए बता दें कि मई में केनीशा ने सोशल मीडिया छोड़ने का फ़ैसला किया था। उन्होंने एक लंबा नोट लिखा था,जिसमें कहा था कि वह अब खुद को समझा-समझाकर थक गई हैं,क्योंकि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा था। केनीशा ने लिखा था,आम जनता,सिनेमा इंडस्ट्री,कमेंट करने वाले,जो लोग उन्हें प्यार करते हैं,नापसंद करते हैं,उनका बचाव करते हैं,उनका मज़ाक उड़ाते हैं या उनकी जिंदगी पर अपना हक जताते हैं अब वह पूरी तरह से आपके हैं। अब कोई सफ़ाई नहीं दी जाएगी। कोई बचाव नहीं होगा। ऐसी लड़ाइयाँ अब नहीं लड़ूँगी जो कभी मेरी थीं ही नहीं। इसलिए आज,मैं इसका विरोध करना छोड़ रही हूँ। मैं उन जगहों पर अच्छाई साबित करने की कोशिश छोड़ रही हूँ जहाँ लोग उसे गलत ही समझना चाहते हैं। मैंने चेन्नई छोड़ दिया है,मैंने हार मान ली है। मैंने अपने संगीत, अपनी थेरेपी और उन सभी चीज़ों को छोड़ दिया है जो अब तक मेरी जिंदगी का हिस्सा थीं। मुझे लगता है कि इंसान उसे तोड़ सकता है जिसे भगवान ने बनाया है। ऑनलाइन बुलीइंग, हेरफेर और जादू-टोने की वजह से मैं यह सब छोड़ रही हूँ। और इसके साथ ही, मैं इंस्टाग्राम और सभी सोशल प्रोफ़ाइल से लॉग ऑफ़ कर रही हूँ, जब तक कि भगवान की जीत न हो जाए। मैं अपने सभी दोस्तों, परिवार और शुभचिंतकों से मुझे ज़रूरी प्राइवेसी देने का अनुरोध करती हूँ। आज से : फेमिनिज़्म,तुम्हारी जीत हुई। खुशी, तुम्हारी हार हुई। प्यार और रोशनी। इससे पहले,कनीशा ने रवि मोहन के साथ अपने कथित रिश्ते से जुड़े कुछ वीडियो भी अपलोड किए थे। हालाँकि,बाद में उन्होंने वे वीडियो हटा दिए।

रवि किशन के वायरल मीम पर टी-सीरीज ने बनाया गाना,पूरे देश को पगला देंगे भोजपुरी स्टार

मिर्जापुरः द मूवी एक्टर रवि किशन के मीम इंटरनेट पर खूब वायरल होते हैं। हालांकि,अब उनके एक वायरल मीम पर टी-सीरीज पूरा का पूरा म्यूजिक वीडियो लेकर आ रहा है। रवि किशन मीम की दुनिया के किंग बन चुके हैं। भोजपुरी स्टार के डांस से लेकर उनके मुंह से निकले शब्द तक इंटरनेट पर धड़ाधड़ वायरल होते हैं, जिस पर लाखों रील्स बन चुकी हैं। अब आधी ऑडियंस पर अपना जादू चला चुके रवि किशन ने ये कसम खा ली है कि वह अपने आने वाले गाने से अब पूरे देश को पगला कर ही दम लेंगे।रवि किशन के स्टेप फॉलो करते हुए तो इंस्टाग्राम पर तो हम लोगों को देख ही चुके हैं,लेकिन अब राज शमानी के पॉडकास्ट में मुंह से निकले शब्द मनी फॉलो माय ब्रदर पर अब एक पूरा गाना बनने वाला है। रवि किशन के मनी फॉलो माय ब्रदर पर कई मीम्स बने थे। अब इसका ऑफिशियल ट्रैक दर्शकों को पक्का पगला देगा,जिसकी एक झलक भी सामने आ चुकी है। टी-सीरीज ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर रवि किशन के म्यूजिक वीडियो का एक छोटा सा टीजर शेयर किया। जिसमें कार में एक मां और बच्चा बैठे हैं। बच्चे का पढ़ाई में कोई इंटरस्ट नहीं होता, ऐसे में जब मां बच्चे से उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है, तो लड़का बोलत है पूरे देश को पगला दूंगा,अभी कुछ पेश किया है सुनो। जिसके बाद कैमरा घूमता है और रवि किशन मनी फॉलो माय ब्रदर मीम बोलते हुए दिखाई देते हैं।

खेल समाचार

डब्ल्यूसीएल सीजन 3 में बड़ा बदलाव पोंटिंग की एंट्री वॉर्नर को मिली टीम की कमान

मेलबर्न,08 सितम्बर 2026। एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार,ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के मालिक के तौर पर टीम से जुड़ गए हैं। वहीं, तूफानी ओपनर डेविड वॉर्नर को आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ लेजेंड्स सीज़न 3 के लिए कप्तान बनाया गया है।
डब्ल्यूसीएल ने मेलबर्न में एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया चैंपियंसः ए न्यू एरा में फ्रेंचाइजी के लिए एक नए दौर की शुरुआत की। यह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मंगलवार को यूरेका 89 में हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ लेजेंड्स के कई बड़े नाम शामिल हुए।

पंजाब एफसी ने 2026-27 सीज़न के लिए ब्राज़ीलियाई फ़ॉरवर्ड डिएगो रैपोसो को किया साइन

मोहाली ,08 सितम्बर 2026। पंजाब एफसी ने आने वाले 2026-27 इंडियन सुपर लीग सीज़न से पहले ब्राज़ीलियाई फॉरवर्ड डिएगो हेनरिक ओलिवेरा रैपोसो को साइन करने की घोषणा की है। बाएं पैर से खेलने वाले इस अटैकर ने 31 मई, 2027 तक का करार किया है। डिएगो रैपोसो ने पिछली बार बुल्गारिया की टॉप-डिविजन टीम एफसी लोकोमोटिव सोफिया के लिए खेला था और लीग में 19 मैच खेले थे। एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार,अल्फ्रेड प्लानास मोया, जेफ्थे पैट्रिक जेरार्ड बहानाक और राफेल मेस्सी बाउली के बाद इस सीज़न में पंजाब एफसी की यह चौथी विदेशी साइनिंग है।

आईसीसी टी 20 आई रैंकिंग में दीप्ति शर्मा ने लगाई बड़ी छलांग

एशिया कप 2026 में शानदार गेंदबाजी का मिला इनाम

नई दिल्ली,08 सितम्बर 2026। एशिया कप 2026 में शानदार गेंदबाजी का फायदा दीप्ति शर्मा को आईसीसी महिला टी 20 आई रैंकिंग में मिला है। दीप्ति दो पायदान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गई हैं।

एशिया कप 2026 में भारतीय गेंदबाज शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं,जिसका फायदा आईसीसी टी 20 आई रैंकिंग में भी हुआ है। अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने महिला टी 20 आई गेंदबाजों की ताजा रैंकिंग में दो पायदान की छलांग लगाकर छठा स्थान हासिल कर लिया है। टूर्नामेंट में अब तक आठ विकेट चटकाने वाली दीप्ति को उनकी शानदार गेंदबाजी का यह इनाम मिला है। दीप्ति ने एशिया कप 2026 में तीन मुकाबलों में आठ विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं भारतीय स्पिनर एन श्री चरणी सात विकेट के साथ रैंकिंग में पहले स्थान पर बनी हुई हैं।

श्री चरणी नंबर-1 गेंदबाज

दीप्ति शर्मा पिछले साल दिसंबर में आईसीसी महिला टी 20 आई गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 पर थीं। हालांकि,इसके बाद एन श्री चरणी ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। मौजूदा रैंकिंग में श्री चरणी के बाद इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन दूसरे, चार्ली डीन तीसरे, लॉरेन बेल चौथे और साउथ अफ्रीका की नॉन कुलुलेको म्लाबा 5वें स्थान पर हैं। श्री चरणी और दीप्ति के बीच सिर्फ 70 रेटिंग पॉइंट का अंतर है।
इंग्लैंड की लिंसे स्मिथ को एक पायदान का नुकसान हुआ है और वह 7वें स्थान पर खिसक गई हैं। पाकिस्तान की स्पिनर नशरा संधू ने हांगकांग के खिलाफ 7 रन देकर 6 विकेट लेकर नया पाकिस्तानी रिकॉर्ड बनाया। हालांकि,इसके बावजूद वह ताजा रैंकिंग में एक स्थान फिसलकर आठवें नंबर पर पहुंच गईं। पाकिस्तान की सादिया इकबाल पर टॉप-10 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। वह 1 स्थान नीचे खिसककर 10वें स्थान पर चली गई हैं।

स्मृति मंधाना 5वें पायदान पर बरकरार

महिला बल्लेबाजों की आईसीसी टी 20 आई रैंकिंग में भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना का जलवा बरकरार है। वह पांचवें स्थान पर हैं। उनसे आगे कोई भी भारतीय महिला बल्लेबाज नहीं है। टॉप पर ऑस्ट्रेलिया की धाकड़ बल्लेबाज बेथ मूनी का जलवा कायम है। महिला टी 20 आई बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में भारत के तीन बल्लेबाज शामिल हैं। शेफाली वर्मा सातवें और कप्तान हरमनप्रीत कौर 10वें स्थान पर हैं। गौरतलब है कि एशिया कप में स्मृति मंधाना का बल्ला लगातार आग उगल रहा है। हाल ही में उन्होंने हांगकांग के खिलाफ शतक लगाने के साथ ही उनके इंटरनेशनल शतकों की संख्या 18 हो गई। इसी पारी के दौरान उन्होंने मिताली राज को पीछे छोड़कर महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./- 20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका श्रीमती दुलारी देवी आ0/पति स्व0 तुलसी राम सर्राफ जाति, निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-देवीगंज रोड़, शीट नम्बर - 3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1032/8, 1155/2 रकबा 0.001, $0.02^{3/4}$ हे0 / एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3. 2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 11.09.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः 27.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./ 20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती दुलारी देवी आ0/पति स्व0 तुलसी राम सर्राफ जाति निवासी बेलखरिखा, तहसील लखनपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-मणीपुर, शीट नम्बर-11 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 4237/4 रकबा $0.14^{1/2}$ एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 11.09.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः 27.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./ 20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका श्रीमती दुलारी देवी आ0/पति स्व0 तुलसी राम सर्राफ जाति,निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला - बरेजपारा, शीट नम्बर-8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2559/30, 2602/74, 2602 / 75 रकबा $0.00^{1/2}$, 0.01, 0.01 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 11.09.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक :- 27.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ- 20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदिका श्रीमती रश्मि बक्शी पति संजय बक्शी, निवासी महामाया रोड़ अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ0ग0 के द्वारा शीट नम्बर-8 मोहल्ला खरसिया रोड़, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1488/1, 1489/1, 1490/1, 1492/8 रकबा $0.00^{1/2}$, $0.00^{1/4}$, $0.07^{1/2}$, $0.03^{1/4}$ एकड़ भूमि को बैक में बंधक रखकर ऋ ण प्राप्त करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र मय मेंन्टनेश खसरा की प्रतिलिपि सहित पेश किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यादे किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 17.09.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक 03.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /अ-6/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक महेन्द्र कुमार सिंह आ.स्व.महात्मा सिंह निवासी रामानुजगंज रोड संजय पार्क के सामने अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम गंगापुरखुर्द स्थित भूमि खसरा नंबर 160/4 रकबा 0.041 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो में पंजीबद्ध हक त्याग पत्र दिनांक 04.05.2026 के माध्यम से अनावेदकगण का नाम विलोपित किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 16.09.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः- 24/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार लखनपुर ,जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

लखनपुर दिनांक 02/09/2026

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम इरगंवा को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनीजर मरावी आ.बुधनसाव निवासी ग्राम ईरगंवा के द्वारा अपनी माता बुधियारों की मृत्यु दिनांक 15.01.2024 को ग्राम ईरगंवा को मृत्यु होना बताते हुए जन्म / मृत्यु रजिस्टीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) एवं छ.ग. जन्म मृत्यु रजि. नियम 2001 के नियम 9 नियत (3) के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र हेतू आवेदक इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया है जिस पर दिनांक 30.09.2026 को सुनवाई की जानी है ।

आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मे किसी को कोई आपत्ति हो तो वो न्यायालय की पेशी 15-9.26. तक अपना दावा / आपत्ति पेश कर सकता है

नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

सील — तहसीलदार लखनपुर,सरगुजा

10 साल से एक ही जगह पदस्थ अधिकारी कौन?

पदोन्नति के बाद पोस्टिंग ने बढ़ाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन की मुश्किलें

एक ही जगह 10 साल, प्रमोशन के बाद भी पसंदीदा ठिकाना! खाद्य एवं औषधि प्रशासन में पोस्टिंग सिस्टम पर सवाल

खाद्य विभाग में 'दस साल वाली परंपरा'! एक ही जगह लंबे समय से जमे अधिकारियों की नाम ने मचाई हलचल

एक ही संभाग में वर्षों से जमे अधिकारियों की सूची ने खोली पदस्थापना व्यवस्था की परतें,पदोन्नति के बाद भी पसंदीदा जगह मिलने पर उठे सवाल...

अभिहित अधिकारी से लेकर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी तक के नाम आए सामने...

धमतरी में 10 साल से अधिक पदस्थापना का दावा, अनुसूचित और मैदानी क्षेत्र के अनुपात पर भी सवाल...

-न्यूज डेस्क-

अंबिकापुर/रायपुर,08 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर उठ रहे सवाल अब केवल स्थानांतरण तक सीमित नहीं रह गए हैं,विभाग में लंबे समय से एक ही संभाग अथवा क्षेत्र में पदस्थ रहने वाले अधिकारियों को लेकर सामने आई सूची ने पूरी पदस्थापना व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर ऐसे समय में जब विभाग में पदोन्नति के बाद अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं की गई हैं,यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या पदोन्नति के बाद वास्तव में रोटेशन की नीति लागू हुई या कई मामलों में अधिकारी फिर अपने परिचित क्षेत्र के आसपास ही बने रहे?

सूत्रों से सामने आई जानकारी में अभिहित अधिकारी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नाम तथा उनकी पूर्व और वर्तमान पदस्थापना का विवरण शामिल है,इसी सूची में एक अधिकारी के धमतरी में दस वर्ष से अधिक समय से पदस्थ रहने का दावा भी सामने आया है,मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि खाद्य एवं औषधि प्रशासन सीधे आम आदमी की थाली,खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा विभाग है,ऐसे संवेदनशील विभाग में अधिकारियों की लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में पदस्थापना को लेकर पारदर्शिता,रोटेशन और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

10 साल वाले अभिहित अधिकारियों की सूची में सामने आए नाम-सूत्रों से प्राप्त पदस्थापना सूची के अनुसार अभिहित अधिकारियों के संबंध में निम्न विवरण सामने आया है,उमेश वर्मा बलौदाबाजार से महासमुंद, सवैरा यादव रायपुर से धमतरी,अक्षय सोनी धमतरी से बलौदाबाजार,मोहित बेहरा बिलासपुर से जांजगीर-चांपा, सुधा चौधरी सारंगढ़ से रायगढ़,मुकेश साहू कवर्धा से कवर्धा सूत्रों से मिली सूची में इन नामों के साथ पूर्व एवं वर्तमान पदस्थापना स्थल का उल्लेख किया गया है,इनमें मुकेश साहू का कवर्धा से कवर्धा दर्ज होना अलग से ध्यान आकर्षित करता है,यदि पदस्थापना में स्थान वही है तो विभागीय आदेश में इसके पीछे दर्ज प्रशासनिक कारण क्या हैं,यह जानना जरूरी हो जाता है,क्या पद में परिवर्तन हुआ? क्या दायित्व बदला गया? क्या प्रशासनिक आवश्यकता के कारण उसी स्थान पर रखा गया? इन सवालों का जवाब संबंधित पदस्थापना आदेश से ही स्पष्ट हो सकता है।

पदोन्नति के बाद भी पोस्टिंग पर सवाल-विभाग में पदोन्नति के बाद हुई पदस्थापनाओं को लेकर भी चर्चा तेज है,सूत्रों का कहना है कि लंबे समय से एक ही संभाग में काम कर रहे कुछ अधिकारियों को पदोन्नति के बाद नई जिम्मेदारी मिली और उनके स्थान बदले गए,लेकिन कई मामलों में यह सवाल बना हुआ है कि नई पदस्थापना किस आधार पर तय की गई,यही वजह है कि अब केवल वर्तमान पदस्थापना देखने के बजाय अधिकारियों की पिछले दस वर्षों की पूरी पोस्टिंग हिस्ट्री सामने लाने की जरूरत महसूस की जा रही है,किस अधिकारी ने किस जिले में कितने वर्ष बिताए? कितनी बार स्थानांतरण हुआ? कितने समय तक अतिरिक्त प्रभार रहा? पदोन्नति से पहले कहां पदस्थ थे? पदोन्नति के बाद कहां भेजे गए? क्या पदोन्नति के बाद भी उसी संभाग में रखा गया? यदि इन सभी सवालों का जवाब एक साथ सामने आ जाए तो पदस्थापना व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर स्वतः स्पष्ट हो सकती है।

अनुसूचित क्षेत्र बनाम मैदानी क्षेत्र...अनुपात पर भी सवाल-सूत्रों से प्राप्त जानकारी में अनुसूचित क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में पदस्थापना के अनुपात को लेकर भी सवाल उठाया गया है,कहा गया है कि दोनों क्षेत्रों के बीच पदस्थापना का अनुपात संतुलित नहीं है,साथ ही यह भी सवाल उठाया गया है कि प्रथम पदोन्नति के पूर्व निर्धारित अनुपात का पालन हुआ या नहीं,यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि शासन अथवा विभाग ने अनुसूचित क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर कोई निर्धारित नीति या अनुपात तय किया है,तो उसका पालन सभी अधिकारियों के मामले में समान रूप से होना चाहिए, यदि अनुपात का पालन नहीं हुआ तो इसकी वजह क्या रही? क्या विभाग के पास इसका कोई प्रशासनिक आदेश है? क्या सक्षम स्तर से छूट दी गई? यदि छूट दी गई तो किन परिस्थितियों में? इन सवालों का जवाब विभागीय रिकॉर्ड से ही मिलना चाहिए।

'दस साल' केवल एक आंकड़ा नहीं, व्यवस्था का आईना-किसी अधिकारी का लंबे समय तक एक ही जगह पदस्थ रहना अकेले में किसी अनियमितता का प्रमाण नहीं माना जा सकता,प्रशासनिक आवश्यकता, पद की प्रकृति,अधिकारियों की उपलब्धता और शासन के आदेश जैसे कई कारण हो सकते हैं,लेकिन जब एक विभाग में लंबे समय तक पदस्थ रहने वाले अधिकारियों की सूची सामने आती है और उसी विभाग में स्थानांतरण व पदोन्नति के बाद की पोस्टिंग को लेकर सवाल उठते हैं, तब पूरी व्यवस्था की समीक्षा जरूरी हो जाती है, खाद्य एवं औषधि प्रशासन में अधिकारियों की भूमिका केवल कार्यालय तक सीमित नहीं है,खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, नमूने लेना,मिलावट के मामलों में कार्रवाई,जांच प्रक्रिया और न्यायालयीन प्रकरणों की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण दायित्व भी इसी व्यवस्था का हिस्सा हैं, ऐसे में लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में रहने वाले अधिकारियों की पदस्थापना का रिकॉर्ड सार्वजनिक होना पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है।

सबसे बड़ा सवाल...क्या विभाग में पोस्टिंग का कोई 'रोटेशन सिस्टम' है?-पूरे मामले का सार यही है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में अधिकारियों की पदस्थापना के लिए यदि स्पष्ट और समान रोटेशन नीति है तो उसे सार्वजनिक किया जाए,यदि नीति है तो पिछले वर्षों में उसका कितना पालन हुआ,यह भी बताया जाए,यदि किसी अधिकारी को दस वर्ष से अधिक समय तक एक ही क्षेत्र में रखा गया तो उसके पीछे क्या कारण था,यह भी स्पष्ट किया जाए,और यदि पदोन्नति के बाद किसी अधिकारी को उसी क्षेत्र में रखा गया तो उस निर्णय का प्रशासनिक आधार क्या था,यह भी सामने आना चाहिए, क्योंकि सवाल किसी एक अधिकारी का नहीं है-सवाल उस व्यवस्था का है,जिसमें एक संवेदनशील विभाग के अधिकारी वर्षों तक एक ही क्षेत्र में पदस्थ रह सकते हैं और फिर पदोन्नति के बाद उनकी नई पोस्टिंग को लेकर भी सवाल उठते हैं, अब जरूरत आरोप-प्रत्यारोप की नहीं,बल्कि दस वर्षों का पदस्थापना रिकॉर्ड सामने रखकर व्यवस्था की पारदर्शिता साबित करने की है।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की सूची भी सवालों में...

सूत्रों से सामने आई जानकारी केवल अभिहित अधिकारियों तक सीमित नहीं है,वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की सूची में भी तीन नाम दर्ज हैं विजेंद्र भारती रायपुर से बलौदाबाजार,ऋचा शर्मा दुर्ग से दुर्ग,साधना चंद्राकर रायपुर से राजनांदगांव,यहां ऋचा शर्मा का दुर्ग से दुर्ग दर्ज होना भी पदस्थापना व्यवस्था को लेकर सवाल पैदा करता है,यदि अधिकारी का पद या दायित्व बदला है और प्रशासनिक आदेश के तहत उन्हें उसी स्थान पर रखा गया है तो वह आदेश ही पूरी स्थिति स्पष्ट कर सकता है, सवाल यह नहीं कि किसी अधिकारी को एक ही जिले में रखना गलत है या सही,असली सवाल यह है कि क्या विभाग के सभी अधिकारियों के लिए एक समान पदस्थापना नीति लागू होती है?

धमतरी में दस साल से अधिक...सबसे बड़ा सवाल...

इस पूरी सूची में सबसे गंभीर जानकारी फनेश्वर पिथौरा के संबंध में सामने आई है,उपलब्ध जानकारी में उनके धमतरी में दस साल से अधिक समय से पदस्थ होने का उल्लेख किया गया है,यदि विभागीय सेवा अभिलेखों से यह तथ्य सही साबित होता है तो यह निश्चित रूप से प्रशासनिक समीक्षा का विषय है, एक अधिकारी यदि दस वर्ष या उससे अधिक समय तक एक ही क्षेत्र में पदस्थ रहता है तो स्वाभाविक रूप से कई सवाल पैदा होते हैं क्या विभाग में अधिकारियों के लिए रोटेशन नीति है? क्या लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ अधिकारियों की समय-समय पर समीक्षा होती है? क्या ऐसी लंबी पदस्थापना के लिए सक्षम स्तर से अनुमति आवश्यक है? यदि अनुमति दी गई थी तो उसके कारण क्या थे? और सबसे बड़ा सवाल...क्या विभाग के सभी अधिकारियों को समान अवसर और समान स्थानांतरण नीति का लाभ मिलता है? इन सवालों का जवाब किसी आरोप या बयान से नहीं, बल्कि विभागीय सेवा अभिलेख और पदस्थापना आदेश से मिलना चाहिए।

सूचना सार्वजनिक हो तो कई सवाल अपने आप खत्म होंगे...

विभाग चाहे तो इस पूरे विवाद को आसानी से समाप्त कर सकता है,इसके लिए पिछले दस वर्षों का संभागवार पदस्थापना रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जा सकता है,रिकॉर्ड में प्रत्येक अधिकारी के लिए पहली नियुक्ति और पदस्थापना,जिलेवार पदस्थापना अवधि,संभागवार कार्यकाल,स्थानांतरण आदेश, अतिरिक्त प्रभार,पदोन्नति की तारीख,पदोन्नति के बाद मिली पदस्थापना,वर्तमान पदस्थापना,अनुसूचित एवं मैदानी क्षेत्र में बिताई गई अवधि जैसी जानकारी सामने रखी जा सकती है,इसके बाद यह बहस अनुमान और चर्चाओं से निकलकर दस्तावेजों पर आ जाएगी।

नाम सामने आए हैं,अब रिकॉर्ड सामने आना चाहिए...

सूत्रों से मिली सूची में उमेश वर्मा,सवैरा यादव,अक्षय सोनी,मोहित बेहरा,सुधा चौधरी,मुकेश साहू,नितेश मित्रा,विजेत भारती,ऋचा शर्मा,साधना चंद्राकर और फनेश्वर पिथौरा के नाम सामने आए हैं,वहीं फोरवर पियौरा के धमतरी में दस वर्ष से अधिक समय से पदस्थ रहने की जानकारी भी दी गई है,इनमें से किसी अधिकारी की पदस्थापना अवधि या स्थानांतरण को अपने आप में अनियमितता मानना उचित नहीं होगा। वास्तविक स्थिति विभागीय सेवा अभिलेख, शासन के स्थानांतरण आदेश और लागू नियमों की जांच के बाद ही सामने आएगी,लेकिन सवाल अब उठ चुका है और वह भी सीधे पदस्थापना व्यवस्था को लेकर।

एक करोड़ की जमीन के लिए दामाद ने ससुर को मारा,शव ठिकाने लगाते तीन गिरफ्तार

रायपुर,08 सितम्बर 2026। रायपुर में पारिवारिक विवाद ने एक खौफनाक वारदात का रूप ले लिया। रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट के बीच एक दामाद पर अपने ही ससुर की हत्या करने का आरोप लगा है। वारदात के बाद आरोपी अपने दो साथियों के साथ शव को ठिकाने लगाने के लिए टाटा मैजिक वाहन में लेकर निकला था। हालांकि, पुलिस की सतर्कता के कारण उनकी योजना कामयाब नहीं हो सकी और हत्या का पूरा मामला सामने आ गया।

पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध टाटा मैजिक दिखी

पूरा मामला राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक 4 सितंबर को धरसींवा, खमतराई और उरला थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम रायपुर-बिलासपुर रोड पर पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान टीम की नजर एक संदिग्ध टाटा मैजिक वाहन पर पड़ी। पुलिस ने संदेह के आधार पर वाहन को जांच के लिए रोकने की कोशिश की।

पुलिस को देखकर मौके से फरार हुए आरोपी

जांच के दौरान टाटा मैजिक के साथ दोपहिया वाहन पर दो युवक भी नजर आए। पुलिस द्वारा वाहन रोककर पूछताछ और जांच शुरू किए जाने पर दोनों बाइक सवार युवक और टाटा मैजिक चला रहा व्यक्ति मौके से फरार हो गए। उनकी इस हरकत से पुलिस का संदेह और गहरा गया।

छत्तीसगढ़ में बदहाल सड़कें और जर्जर स्कूल...भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन

रायपुर,08 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने राज्य में शिक्षा व्यवस्था,सड़कों की जर्जर स्थिति और कानून-व्यवस्था को लेकर साय सरकार को कटघरे में खड़ा किया। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा सत्र शुरू हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार बच्चों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे पा रही है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश भर में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छात्र-छात्राएं स्कूल भवन,किताबों और शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। उन्होंने सरगुजा के शिवपुर का जिक्र करते हुए कहा कि एकलव्य विद्यालय की छात्राएं

3 महीने से बिजली बंद रहने,मेस में खराब खाना मिलने और पढ़ाई न होने के कारण 40 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर से मिलने निकलीं। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि समस्याओं को हल करने के बजाय बच्चों के आंदोलनों को कांग्रेस प्रायोजित बताना बेहद शर्मनाक है। प्रदेश में सड़कों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए बैज ने कहा कि राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर,सरगुजा और जशपुर तक एक भी सड़क ऐसी नहीं बची है,जिस पर आसानी से चला जा सके। पिछले ढाई सालों में सरकार ने न तो नई सड़कें बनाई और न ही पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई। सड़कों के गड्ढे सरकार की नाकामी को दर्शाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजधानी में सड़कों की बदहाली उजागर करने पर एक पत्रकार को जेल तक भेज दिया गया।

आज को होगी साय कैबिनेट की बैठक कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

रायपुर,08 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2026 को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों के साथ प्रदेश के जनहित और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।

बैठक को सरकार के आगामी फैसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैबिनेट के सामने कई विभागों के प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है, जिन पर विचार-विमर्श के बाद सरकार निर्णय ले सकती है। हालांकि बैठक के एजेंडे

को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और सरकार कौन से बड़े फैसले लेती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। बैठक के बाद स्वीकृत प्रस्तावों से संबंधित विस्तृत जानकारी और आदेश जारी होने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग का बड़ा प्रशासनिक बदलाव,डीईओ के तबादले

रायपुर,08 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले की सूची जारी कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने मंगलवार देर शाम तबादला आदेश जारी किया। जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी। अब विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कई जिला शिक्षा अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक जरूरतों और विभागीय कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। तबादले के बाद संबंधित अधिकारियों को नए पदस्थापना

स्थल पर जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही पूरी करने को कहा है। राज्य सरकार समय-समय पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिकारियों के तबादले करती रहती है। जिला शिक्षा अधिकारी जिले में स्कूलों के संचालन,शिक्षकों से जुड़े मामलों, परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हैं। ऐसे में डीईओ स्तर पर हुए बदलाव को शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले को लेकर बीते दिनों से ही चर्चाएं तेज थीं। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर नई पदस्थापना की जानकारी सार्वजनिक कर दी है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)